https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'वे जितना कीचड़ उछालेंगे, हमारे लिए कमल का खिलना उतना ही आसान हो जाएगा'

वर्ष-12, अंक-24 16-31 दिसम्बर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

गुजरात चुनाव

'कांग्रेस को बहा ले जाएगी भाजपा की महालहर'

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत

पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने की अफवाह

'आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है'

गुजरात विधानसभा चुनाव–2017 के निमित्त आयोजित जनसभाओं के दृश्य

देवभूमि द्वारका में विशाल रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

तापी महिला बैठक में उल्लसित महिलाओं का एक दृश्य

कडाना, महिसागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कच्छ में एक भव्य रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

मांगरोल, जूनागढ़ में अन्य नेताओं के साथ जनाभिवादन स्वीकार करते हुए श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 वे जितना कीचड़ उछालेंगे, हमारे लिए कमल का खिलना उतना ही आसान हो जाएगा : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 नवंबर को गुजरात के भुज, जसदण, धारी और कड़ोदरा में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि जनता के प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे पूर्व विश्वास है कि 150 से भी...

वैचारिकी

भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था 20

श्रद्धांजलि

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय 22

लेख

पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने की अफवाह 23

अन्य

'कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न ही आम जनता के... 08

'गुजरात की जनता ने कांग्रेस को उसकी नकारात्मक राजनीति... 12

कृषि शिक्षा बजट में वर्ष 2013-14 की तुलना में 47.4 प्रतिशत... 17

दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.3 प्रतिशत 18

भारत और सिंगापुर के बीच नौसेनाओं के सहयोग पर अहम समझौता 25

'15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की योजनाओं से जुड़े' 27

डिजिटल प्रौद्योगिकी एक क्रांतिकारी साधनः नरेन्द्र मोदी 29

आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा हैः नरेंद्र मोदी 30

'जल्दी से जल्दी श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई होनी चाहिए 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 भाजपा सरकार ने कर्फ्यू-मुक्त एवं टैंकर-मुक्त शासन देने का काम किया है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

14 उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत

उत्तर प्रदेश के गत विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनावों में भी भारतीय...

सरकार की उपलब्धियां

17 राष्ट्रपति ने दी दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी

भारत के राष्ट्रपति ने 23 नवंबर को दिवाला एवं...

19 दूसरी बार जज चुने गए दलवीर भंडारी

भारत के श्री दलवीर भंडारी को नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिर से जज के तौर पर चुन लिया गया। जस्टिस दलवीर भंडारी...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

हमारी सरकार की योजनाएं सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने वाली रही हैं।

@AmitShah

एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दुनिया में देश का मान-सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर जन-जन का अपमान करने में लगी है।

@arunjaitley

राहुल गांधी ने 18 फीसदी की एक दर वाले जीएसटी का सुझाव दिया है। यह 18 फीसदी की सीमा के सुझाव से अलग है। यह बड़ा मूर्खतापूर्ण विचार है। क्या एक हवाई चप्पल और एक बीएमडब्ल्यू कार पर एक कर की समान दर को लगाया जा सकता है?

facebook

प्रदेश में आदि शंकराचार्य के दर्शन से समाज को परिचित कराने और उनकी अष्टधातु की विशाल प्रतिमा के निर्माण के लिए घर-घर से धातु संग्रहण के लिए 19 दिसंबर से #एकात्म_यात्रा प्रारम्भ होगी। एकात्म यात्रा ओंकारेश्वर, उज्जैन, पचमठा, अमरकंटक से एक साथ प्रारम्भ होगी। सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एकता में आदि गुरू के अप्रतिम योगदान के संबंध में जनजागरण, अद्वैत वेदांत दर्शन में प्रतिपादित जीव, जगत, जगदीश के एकात्म बोध के प्रति जन-जागरण करना यात्रा का प्रयोजन है। एकात्म यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालते हुए उनके दर्शन से समाज को अवगत कराया जायेगा। यात्रा के अंतिम दिन 22 जनवरी, 2018 को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची अष्ट धातु की विशाल प्रतिमा का शिलान्यास किया जायेगा।

— शिवराज सिंह चौहान

प्रदेश में अब, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित 7 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से जयपुर शहर में अंतराष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी उपलब्ध हैं। राजस्थान में पर्यटन, अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं आधारिक संरचनाओं को प्रबल बनाने के लिए हमारी सरकार पहले दिन से एकजुट होकर काम कर रही है और इस कड़ी मेहनत का फल राजस्थान के विकास में साफ़ नज़र आ रहा है।

— वसुंधरा राजे

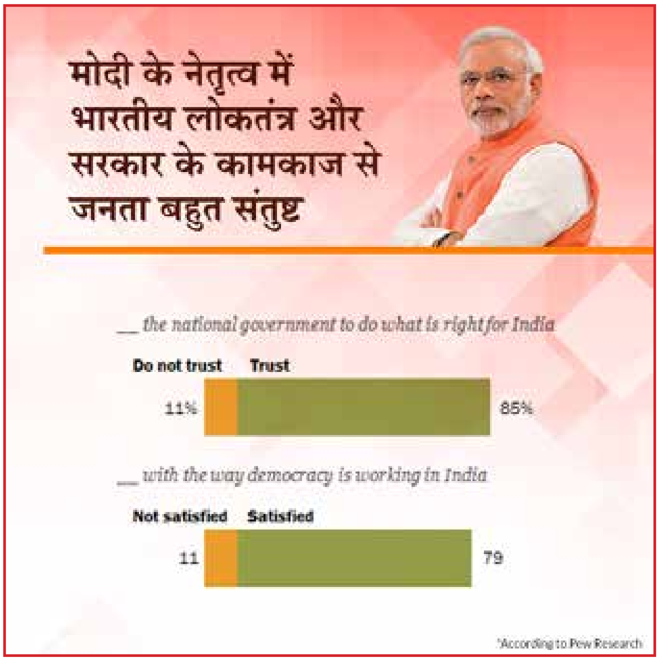

'कमल संदेश' की ओर से सुधी पाठकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं!

राजनीति के हाशिये पर वंशवादी कांग्रेस

राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष होंगे। इसमें न तो कोई आश्चर्य होने की बात है और न ही कांग्रेस के लिए इसका कोई विशेष महत्व है। यह सबको पता ही था कि वे सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी हैं तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में वे पहले से ही पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे थे। इसलिए यह एक तरह से पुराने नेतृत्व को ही जारी रखने का निर्णय है तथा यह केवल कागजी कार्रवाई भर है, जिसमें कुछ भी नया नहीं दिखता। राहुल गांधी द्वारा अपनी मां सोनिया गांधी का स्थान लेना इसी बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों ने सोनिया–राहुल ही कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों से राहुल द्वारा अपनी मां से कांग्रेस की कमान लेने की बात कई बार चर्चा में आई, परंतु निरंतर हार के कारण कांग्रेस के हाथ उत्सव मनाने योग्य अवसर नहीं लगा। 'उचित अवसर' नहीं मिलने के कारण राहुल का अध्यक्ष बनना बार–बार टलता रहा। अंततः कांग्रेस नेतृत्व ने इस औपचारिकता को हिमाचल एवं गुजरात के चुनाव परिणाम घोषित होने से पूर्व ही पूरा कर लेना ठीक समझा है। अब जबकि हिमाचल एवं गुजरात के आसन्न हार को देखते हुए फिर से मौका चुकने से बेहतर राहुल को अध्यक्ष पद पर काबिज कराने का निर्णय कांग्रेस ले चुकी है, ऐसे में पार्टी ने वंशवाद की जकड़ से संगठन को बचाने का एक और अवसर खो दिया है।

पिछले 19 वर्षों से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रही। वे अब तक की सबसे लम्बे समय तक इस पद पर रहने वाली अध्यक्ष हैं, यहां तक कि इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी से भी कहीं लम्बे समय तक। कांग्रेस जिसमें हर वर्ष अध्यक्ष चुनने की परंपरा थी, अंततः वंशवादी राजनीति की शिकार हो गई। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद सीताराम केसरी को पद से हटाकर प्राप्त किया। सीताराम केसरी कांग्रेस में वंशवादी राजनीति की पुनर्स्थापना में बाधा बने हुए थे। कांग्रेस के लोग आज भी नरसिंह राव को वंशवादी राजनीति से उलट चलने के लिए माफ नहीं कर पाये तथा सीताराम केसरी को तो बाद में जबरन पद से हटाना पड़ा था। यही कारण है कि राहुल के पदारोहण को और अधिक टालना वंशवादी राजनीति के लिए घातक माना जा रहा था।

> कांग्रेस का भाग्य एक विशेष वंश की नियति से बंध चुका है तथा हर कांग्रेसी इसका असहनीय भार अपने कंधों पर महसूस करता है। जो इस स्थिति से कांग्रेस को उबारना भी चाहते हैं उन्हें पता है पार्टी में वंशवाद पर प्रश्न खड़े करना ईशनिन्दा की तरह है। जो पार्टी को बचाना चाहते हैं उन्हें भी पता है कि वंशवाद के चक्कर में संगठन की स्थिति जर्जर हो चुकी है और अब पुनः इसमें लोकतंत्र को स्थापित करना टेढ़ी खीर है।

वंशवाद की जकड़ में कांग्रेस का जनाधार तेजी से कमजोर हुआ है, जिसके कारण देश की राजनीति में इसे मुंह की खानी पड़ रही है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल जैसे दिग्गजों द्वारा पल्लवित–पोषित कांग्रेसी संस्कृति के विपरीत लोकतंत्र में वंशवाद को तर्कसंगत बताने में आज के कांग्रेसी सबसे आगे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस वंशवाद से आगे कुछ भी देखने में असमर्थ है, जिससे यह संगठन अब एक 'पारिवारिक संस्था' में परिवर्तित हो चुका है। पार्टी पर लगातार वंशवादी नियंत्रण से इसका संगठन काफी कमजोर हो चुका है, फलतः यह चुनाव–दर–चुनाव हार का मुंह देखने को मजबूर है। अब यह मुख्यधारा की पार्टी से भारतीय राजनीति के हाशिये पर जाने की अपनी यात्रा पर निकल चुकी है।

कांग्रेस का भाग्य एक विशेष वंश की नियति से बंध चुका है तथा हर कांग्रेसी इसका असहनीय भार अपने कंधों पर महसूस करता है। जो इस स्थिति से कांग्रेस को उबारना भी चाहते हैं उन्हें पता है पार्टी में वंशवाद पर प्रश्न खड़े करना ईशनिन्दा की तरह है। जो पार्टी को बचाना चाहते हैं उन्हें भी पता है कि वंशवाद के चक्कर में संगठन की स्थिति जर्जर हो चुकी है और अब पुनः इसमें लोकतंत्र को स्थापित करना टेढ़ी खीर है। आज का युवा जो लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आदर्श मानता है, उनके लिए उन वंशवादी सिद्धांतों जिसमें स्वतंत्रता पूर्व के विशाल कांग्रेस को सत्ता केंद्रित चाटुकारों का समूह बना दिया है, उसको समर्थन देना कठिन होगा। कांग्रेस को अब तक समझ लेना चाहिए था कि उसकी निरंतर हार का मुख्य कारण वंशवादी राजनीति से चिपके रहने की उसकी 'बालहठ' ही है। इस 'बालहठ' से न तो कांग्रेस संगठन में नए प्राण फूंके जा सकते हैं, न ही इसकी नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। अब जबकि कांग्रेस इस सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं, इसका पुनरूत्थान अनिश्चित प्रतीत होता है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

वे जितना कीचड़ उछालेंगे, हमारे लिए कमल का खिलना उतना ही आसान हो जाएगा : नरेन्द्र मोदी

विदित हो कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर 9 दिसंबर को मतदान हुए। वहीं 93 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 14 दिसंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में मतों की गिनती 18 दिसंबर को होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 नवंबर को गुजरात के भुज, जसदण, धारी और कड़ोदरा में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि जनता के प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे पूर्व विश्वास है कि 150 से भी अधिक सीटों पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार करके गुजरात की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन गुजरात की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। जनसभाओं को संबोधित करने से पूर्व उन्होंने कच्छ में मां आशापुरा देवी से आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं से भी मुलाक़ात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने विकास के पथ पर अविरल गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष हम पर कीचड़ उछाल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कीचड़ उछालने वालों का दिल से आभार मानता हूं, क्योंकि वे जितना कीचड़ उछालेंगे, हमारे लिए कमल का खिलना उतना ही आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात मेरी मेरी मां है, मेरी आत्मा है। दिल्ली में बैठे हुए भी मैं ऐसी भूल नहीं कर सकता कि गुजरात को फायदा न हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज एक ऐसी सरकार जिसके लिए जनता का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, हमने सबके हित के लिए काम किया।

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ वंशवाद। उन्होंने कहा कि यह विकासवाद बनाम वंशवाद का चुनाव है और गुजरात की जनता वंशवाद को कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विकास हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कच्छ के रेगिस्तान में केसर खिलाने का काम किया, पानी पहुंचाने प्रबंध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीयत है, न नीति है, न नेता है और न ही उनका इस धरती से कोई नाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद करें तो एक ही परिवार का चेहरा नजर आता है, कोई दूसरा नेता उभरकर सामने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को याद करते हैं तो बोफोर्स याद आता है, टूजी याद आता है, कोयला घोटाला याद आता है, जल-थल-नभ हर जगह जहां कांग्रेस को मौक़ा मिला, वहां उसने भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ एक परिवार की सोचेगा, वो देश के लिए क्या काम करेगा।

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में पहली बार जब जनता मोर्चा की सरकार बनी तो बाबूभाई जसभाई

पटेल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि गुजरात में पहली बार कोई पटेल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर सभी विधायकों को जेल में डाल दिया, विधायकों की खरीद-फरोख्त की और बाबूभाई जसभाई पटेल जी की सरकार गिरा थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने चिमनभाई पटेल के साथ भी धोखा किया। यह भारतीय जनता पार्टी थी जिसने चिमनभाई पटेल का साथ दिया और फिर केशुभाई पटेल जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि गुजरात में भूकंप आया और राहत कार्यों का सहयोग करने के बदले कांग्रेस के कार्यालय से केशुभाई पटेल के खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि चौथे पटेल मुख्यमंत्री के रूप में आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की बागडोर संभाली, लेकिन उनके खिलाफ भी कांग्रेस द्वारा साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चार-चार पाटीदार मुख्यमंत्रियों के खिलाफ साजिश रचकर गुजरात को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा द्वेष, ऐसी ईर्ष्या नहीं देखी, ये समाज को बांटने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ऐसी सोच रखने वाले मोदी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने तो इसमें दुःख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी घर में जन्म लेने के कारण कांग्रेस मोदी को पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वे मेरी गरीबी व गरीबों का मजाक न उड़ाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चायवाले का मजाक उड़ा कर गरीबों का

अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मोदी है, चाय बेचेगा लेकिन देश कभी नहीं बेचेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने, देश के अर्थव्यवस्था से काला-धन, जाली नोट के कारोबार और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन एक साल बाद भी कांग्रेस इसका रोना रो रही है। उन्होंने कहा कि जिनको प्रॉब्लम है, वे कान खोलकर सुन लें, यह सरकार ईमानदारी के मार्ग से हटने वाली नहीं है, जिन्होंने गरीब को लूटा है, उन्हें गरीबों को लौटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने नोटबंदी की तब पता चला कि पाकिस्तान से कैसे पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटा जाता था। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत मेरे सामने आये, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला - मैं देश के लिए और देश की गरीब जनता के लिए लड़ता रहूंगा, भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी।

जीएसटी की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी मंत्री हैं, ये काउंसिल में तो अपनी पूर्ण सहमति देते हैं, लेकिन बाहर आकर विरोध करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी अहंकार के जब भी जरूरत हुई, हमने लोगों की समस्याओं के अनुसार जीएसटी में सुधार किये। उन्होंने कहा कि देश की भाजपा सरकार 125 करोड़ देशवासियों की सरकार है और हम निरंतर देश के लोगों के लिए काम करते हैं, आगे भी जीएसटी को सरल बनाने के लिए यदि और सुधार की जरूरत पड़ी, तो हम करने से नहीं हिचकेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं छोटा था तब घोघा-दहेज रो-रो फेरी सेवा की बात सुनता था, लेकिन इसका उद्‌घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला, आखिर कांग्रेस को इस योजना को पूरा करने से किसने रोका था। उन्होंने कहा कि मैं आपको आज खुशखबरी दे रहा हूं कि घोघा-दहेज रो-रो फेरी की तरह ही कच्छ से मुंबई तक रो-रो फेरी शुरू की शुरुआत की जायेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में 1995 तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने गुजरात के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि गुजरात में इस तरह बिजली पैदा करूंगा कि आम लोगों को भी 24 घंटे बिजली मिले। उन्होंने कहा कि आज गुजरात में घर-घर 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैं इतने पर ही रुकने वाला नहीं हूं, बल्कि मुझे अब आपको बिजली के बिल के बोझ से भी मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि आये दिन अहमदाबाद-राजकोट हाइवे पर दुर्घटनाएं होती रहती थीं, हमने अहमदाबाद राजकोट हाइवे को टू से फोर लेन किया है, अब कोई दुर्घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि अब हाइवे को छः लेन का किया जाएगा, हम गुजरात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीब आदमी भी प्लेन से सफ़र कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात को रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी - सभी चार मार्गों से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया की सभी श्रेष्ठ चीजों को गुजरात में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाया, जिससे सबसे ज्यादा किसानों को और गरीबों को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मूलमंत्र है।

श्री मोदी ने कहा कि राजीव गांधी कहते थे कि सरकार एक रुपया जारी करती है तो गांव तक केवल 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यदि इसकी समझ थी तो इसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा पंजा था जो एक रुपये को 15 पैसे में बदल कर देता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक यही खेल खेला। उन्होंने कहा कि विकास की बात तो उनके गले से नीचे उतरती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र ध्येय गुजरात की जनता को सुख पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विकास, विकास और विकास - यही हमारा मार्ग, मकसद और मंत्र है। उन्होंने कहा कि हम देश के आम नागरिकों के जनजीवन में बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध हैं।

जिनको प्रॉब्लम है, वे कान खोलकर सुन लें, यह सरकार ईमानदारी के मार्ग से हटने वाली नहीं है, जिन्होंने गरीब को लूटा है, उन्हें गरीबों को लौटाना पड़ेगा। हमने नोटबंदी की तब पता चला कि पाकिस्तान से कैसे पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटा जाता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय गुजरात की जो स्थिति थी, इसे हर कोई परिचित है। उन्होंने कहा कि हर तरफ अराजकता और बदहाल क़ानून का साम्राज्य था - पतंग उड़ाने में भी दंगे हो जाते थे, बच्चे के खेल में भी दंगे हो जाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम करती थी, लेकिन आज सब तरफ शांति है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयेंगे, जायेंगे, जीत-हार होती रहेगी लेकिन गुजरात का ताना-बाना नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार गुजरात की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और गुजरात के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगी।

गुजरात की जनता से अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को पहले चरण में मतदान करके आप सभी विनाशकारी शक्तियों को पराजित करें और विकास की गति और तेज करने के लिए राज्य में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। ■

‘कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न ही आम जनता के साथ उनका कोई नाता है’

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवंबर को गुजरात के मोरबी, प्राची, पालिताणा और नवसारी में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और गुजरात की जनता से राज्य के विकास को अवरुद्ध रखने और लगातार गुजरात के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस को विधान सभा चुनाव में सजा देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हम हमेशा जनता के सुख-दुःख के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अगस्त 1979 में मच्छू डैम टूटने से मोरबी शहर तबाह हो गया था तो मैं केरल से यहां जनता-जनार्दन की सेवा के लिए आया। तब की एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी उस वक्त मोरबी आई थी, लेकिन अपने नाक पर रुमाल ढंक कर जबकि आरएसएस एवं जन संघ के कार्यकर्ता मानवता की सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त समाचार पत्र ‘चित्रलेखा’ ने पहले पन्ने पर दो तस्वीरें प्रकाशित की थी – एक तरफ आरएसएस और जन संघ के कार्यकर्ता मानवता की सेवा कर रहे थे जिसे ‘मानवता की महक’ की संज्ञा दी गई, जबकि दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी नाक पर रुमाल रखे हुए जाते हुए दिखाई दे रही थी जिसका कैप्शन था ‘राजकीय गंदगी’। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में रहें, न रहे – हम हमेशा जनता-जनार्दन की भलाई के लिए खड़े रहे रहेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो भगवान् सोमनाथ का भव्य मंदिर न होता, सोमनाथ की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में लहरा न रही होती। उन्होंने कहा कि ये सरदार पटेल थे जिन्होंने भगवान् सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया। उन्होंने कहा कि आज सोमनाथ मंदिर को याद करने वाले क्या अपना इतिहास भूल गए। उन्होंने कहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर सोमनाथ मंदिर बनाए जाने के विचार से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर आने वाले थे, जवाहर लाल नेहरू जी ने उन्हें पत्र लिखकर अपना असंतोष प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरदार पटेल ने नर्मदा परियोजना को लेकर भी सपने संजोए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस सपने को भी पूरा नहीं होने दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष झूठा प्रचार करके जातिवाद का जहर फैला रहा है। जिन्होंने 17 साल एक परिवार की राजनीति की, देश को विकास से महरूम रखा वे हमसे जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले हैंडपंप देने का वादा करती थी और वादा निभाते-निभाते वह तीन-तीन चुनाव निकाल देती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विकास हैंडपंप है, जबकि भारतीय जतना पार्टी का विकास सौनी परियोजना और नर्मदा की पाइपलाइन है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में जातिवाद का जहर फैलाया, भाई-भाई में खाई पैदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी समुदाय का वोट चाहती है, लेकिन उसे पहले यह बताना चाहिए कि उसने इतने सालों तक ओबीसी आयोग को कानूनी वैधता देने की मंजूरी क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि संसद में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक लेकर आये, लोकसभा में यह पारित हो गया, क्योंकि वहां हमारी बहुमत है लेकिन कांग्रेस ने इसे राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को पारित होने में सहयोग न करके ओबीसी समुदाय के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में आपका अपना बैठा है, वह आपके खिलाफ ऐसे किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि आपके लिए यदि मुझे 50 बार भी विधेयक लाना पड़े तो लाऊंगा और इसे संवैधानिक दर्जा देकर रहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक तो आपको आपका हक़ नहीं दिया और जिसने आपको हक़ देना चाहा, उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 70 वर्षों तक देश को लूटा है, उनको सजा देने का वक्त आ गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए शासन के समय अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था और इसमें गुजरात के कई श्रद्धालु शहीद हो गए थे, इसके बावजूद आतंकवादी सीमा पार करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि इस साल भी अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, लेकिन इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि इस बार डेढ़ महीने के भीतर ही हमने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि यह नेतृत्व-नेतृत्व का फर्क है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भारतीय नागरिक संकट में फंसते हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाती है और उन्हें वापस अपने देश लाती है। उन्होंने कहा कि हम ईराक और अफगानिस्तान में आतंकवादियों के चंगुल में फंसे हुए अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक छुड़ा कर दिल्ली लाने में समर्थ रहे। उन्होंने कहा कि हमने श्रीलंका में भी फांसी की सजा पाए हुए हमारे मछुआरे भाइयों की सकुशल वापसी कराई।

श्री मोदी ने कहा कि लातूर में भूकंप आया, जम्मू-कश्मीर में भूकंप आया, केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई, तटीय इलाकों में साइक्लोन आया, लेकिन फिर से खड़ा होने में इन क्षेत्रों को कई साल लग गए। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी भूकंप आया, लेकिन हमने आपदा को अवसर में बदलकर दिखाया। उन्होंने कहा कि विपत्ति को अवसर में बदलना ही गुजरात मॉडल है। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात में ऐसा काम किया है कि 100 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात में हमने पानी की हर बूंद बचाने का अभियान चलाया, क्योंकि हम समझते हैं कि यदि गुजरात में केवल पानी की समस्या हल हो जाय तो गुजरात में इतनी क्षमता है कि वह विश्व को समृद्ध कर सकता है। हमारे लिए विकास चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि हमने लाखों चैकडैम बनाए, लगभग 1,10,00 खेत तालाब बनाए, अकेले सौराष्ट्र में सौनी परियोजना से 115 चैकडैम बने, सौनी परियोजना और नर्मदा परियोजना से पानी कच्छ और सौराष्ट्र तक पहुंचाया, हमने हमने पानी को सौ-सौ मंजिल ऊपर पहुंचाया और जल-संरक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र के किसानों को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि कभी उनके खेतों में पानी आयेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि गुजरात में कृषि आय 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 1700 करोड़ हो गई है, कृषि उत्पादन में दो से तीन गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, हमने चार कृषि विश्वविद्यालय बनाए, हमने पशुधन के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने कहा कि हम आने वाले 100 वर्षों के लिए योजनायें बनाते हैं, केवल चुनाव के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की तरह हम बात नहीं करते, काम करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 6,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लेकर आये हैं, ताकि किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मूंगफली बेचने से ज्यादा किसानों को मूंगफली का तेल बेचने में फायदा होगा, इसी तरह कच्चे आम का अंचार, टमाटर का कैचप बनाने से किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि फिशरमेन को सरकार डीजल वाली बोट के लिए पैसा दे रही है, ताकि वह समुद्र में दूर जाकर मछली पकड़ सकें, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पैसा दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि एक भी किसान इसे अपनाता है तो उसकी आय में लगभग 2 लाख रुपये की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसान तो उत्पादन करता है, लेकिन उसकी आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए हम ये योजना लेकर आये हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय मैंने अनशन पर बैठकर मां नर्मदा के पानी को कच्छ और सौराष्ट्र के सुदूर इलाके तक पहुंचाया, यह सब गुजरात की जनता का स्नेह और आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा की बात ही नहीं की, शायद वे कांग्रेस पार्टी के दवाब में ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो नर्मदा डैम में दरवाजे खोलने को लेकर मनमोहन सिंह जी से मिला था, वे बोले ठीक है, दो महीने बीत गए, फिर मैंने उनसे पूछा तो बोले कि अभी तक नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ महीनों बाद मैंने फिर उनसे पूछा तो फिर वे बोले – अभी तक नहीं हुआ क्या? उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं तो क्या किया जा सकता है! उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री बनने के 17 दिनों में ही दरवाजा खोलने का काम कर दिया और मां नर्मदा का पानी आज गुजरात के हर इलाके में पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश पर बोझ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न ही आम जनता के साथ उनका कोई नाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव आपकी सेवा में तत्पर रही है, आपके बीच रही है। जनता से अपील करते हुए कहा कि भूकंप से पहले का कच्छ-सौराष्ट्र देखिये, भूकंप से बाद का देखिये, नर्मदा और सौनी परियोजना से पहले का कच्छ-सौराष्ट्र देखिये, परियोजना के बाद देखिये, भाजपा से पहले का कच्छ-सौराष्ट्र देखिये, भाजपा के बाद देखिये और तुलना कीजिये। ■

भाजपा सरकार ने कर्फ्यू-मुक्त एवं टैंकर-मुक्त शासन देने का काम किया है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 दिसंबर को गुजरात के कोडिनार, मांगरोल और वेरावल में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से गुजरात के साथ हमेशा अन्याय करने वाली और प्रदेश को विकास से महरूम रखने वाली कांग्रेस को इस विधान सभा चुनाव में सजा देने का आह्वान किया। उन्होंने गुजरात में विकास की गति और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में एवं मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रुपाणी, उप-मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतूभाई वाघाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की।

उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनावों में भाजपा को मिली शानदार सफलता पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की जनता, राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा संगठन पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि 16 में से 14 नगर निगमों में भाजपा की शानदार जीत हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नगर निगम की एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई है और इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी के लोक सभा क्षेत्र अमेठी से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस आवे छे, आवे छे जबकि अमेठी की जनता कहती है कि कांग्रेस जावे छे, जावे छे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात में जीत का दिवास्वप्न देख रही है, जबकि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों की जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेसी नेताओं के चेहरे से नूर उतर गए और जैसे ही काउंटिंग पूर्ण हुई, कांग्रेसी नेता टीवी चैनल से गायब हो गए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट है कि समग्र देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इससे भी बड़ी जीत 18 दिसंबर को गुजरात दर्ज करेगी, जब भारतीय जनता पार्टी 150 से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहरायेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि तीन महीन पहले जीडीपी के आंकड़े आये थे, तभी जीएसटी नया-नया इम्प्लीमेंट हुआ था, तो जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ी सी गिरावट आई। उन्होंने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज होते ही कांग्रेसी नेता टीवी चैनलों पर देश में मंदी आई, मंदी आई की रट लगाने लगे। उन्होंने कहा कि कल जीडीपी के नए आंकड़े आये, भारत की जीडीपी फिर से तेज रफ़्तार से आगे बढ़ चली तो अब कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, आश्चर्यजनक रूप से टीवी चैनलों से भी गायब हो गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़नेवाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा पर आगे बढ़ चला है, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ता कि देश के विकास से कांग्रेस को इतनी बेचैनी क्यों होती है?

कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को

यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह गुजरात में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल विरोध के आधार पर और जातिवाद के आधार पर राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के हर गांव में 24 घंटे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, सड़क, पानी, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी को गुजरात का विकास दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अमेठी में आजादी के बाद से अब तक एक ही परिवार के लोग चुनकर आते रहे हैं। तीन बार से राहुल गांधी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अमेठी में रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, यह पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस परिवार और राहुल गांधी अमेठी में कलेक्ट्रेट ऑफिस तक नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि अमेठी से हजारों युवा रोजगार के लिए पलायन करने को विवश हैं। आखिर राहुल गांधी गुजरात को कौन सा विकास का मॉडल दिखाना चाहते हैं?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गुजरात में जातिवाद का जहर फैलाती आई है, वह आज भी गुजरात में यही कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात के विकास को अवरुद्ध करके रखा था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज गुजरात में विकास की अविरल धारा बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हर सभा में केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विरोध करती है, लेकिन गुजरात के विकास का उसके पास क्या रोडमैप है, इसे नहीं बताती। सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी के प्रवेश को लेकर हुए विवाद पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी ही बातों को गलत बता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद का ज़हर फैलाती है, जबकि भाजपा विकास की सुगंध फैलाती है।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी साबरमती रिवरफ्रंट पर सभा करते हैं और पूछते हैं कि मोदी जी, आपने गुजरात के विकास के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जहां आप खड़े होकर सभा कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन में वह एक गंदा नाला हुआ करता था और आप विकास की बात करते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक साल में 200 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुजरात में किसी ने कर्फ्यू नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने गुजरात में कर्फ्यू-मुक्त एवं टैंकर-मुक्त शासन देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर साढ़े तीन साल में हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए, जबकि सोनिया-मनमोहन की यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपये का घोटाला और भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गुजरात की जनता को हिसाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने नर्मदा परियोजना को क्यों रोक कर रखा, नर्मदा बांध की ऊंचाई क्यों रोकी और गुजरात को उसके हक़ की रॉयल्टी क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास उत्तर देने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 1961 में नर्मदा परियोजना की नींव रखी गई लेकिन जब श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब गुजरात पानी के लिए त्राहि-त्राहि करता था, आज श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से नर्मदा, सौनी एवं सुजलाम-सुफलाम परियोजना के बल पर गुजरात के हर इलाके को पानी मिल रहा है और जल-स्तर में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि जब गुजरात में उनकी सरकार थी, तो उन्होंने गुजरात के विकास के लिए क्या किया?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमने गुजरात में एम्स देने का काम किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाइवे, बुलेट ट्रेन, घोघा-दहेज रो-रो फेरी सेवा, स्मार्ट सिटी सहित कई योजनायें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आते ही गुजरात को उसके हक़ की रॉयल्टी मिलनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए 106 से अधिक योजनायें शुरू की हैं और इन सभी सर्वस्पर्शी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का भी काम किया है।

कांग्रेस हमेशा से गुजरात में जातिवाद का जहर फैलाती आई है, वह आज भी गुजरात में यही कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात के विकास को अवरुद्ध करके रखा था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज गुजरात में विकास की अविरल धारा बहा रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स, ग्रांट इन ऐड, डिजास्टर रिलीफ, लोकल बॉडीज ग्रांट आदि को मिला दिया जाय तो 13वें वित्त आयोग में केंद्र की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने गुजरात को जहां केवल 63,346 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को 1,58,377 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस का ही परिणाम है कि 2014 के बाद देश में हुए लगभग सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात के हर कोने से राज्य की जनता का जो अपार स्नेह व आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, उससे मुझे पूर्ण यकीन है कि भाजपा गुजरात में 150 से ज्यादा सीटों पर निश्चित रूप से विजयी होगी। ■

'गुजरात की जनता ने कांग्रेस को उसकी नकारात्मक राजनीति का माकूल जवाब दिया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 दिसंबर को गुजरात की देवभूमि द्वारका और खंभालिया में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से गुजरात में विकास की गति निरंतर बनाए रखने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन का आह्वान किया। राज्य की जनता द्वारा अभूतपूर्व स्वागत से अभिभूत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात की आम जनता से मिल रहे अद्भुत प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य में 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर एक नया इतिहास रचेगी। इसके पूर्व उन्होंने जगतपति भगवान् द्वारकाधीश के दर्शन किये और पूजा-अर्चना की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अब तक गुजरात की जनता को यह नहीं बता रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसका एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा कि शांति की भूमि गुजरात में कांग्रेस जातिवाद का जहर घोल कर वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता कांग्रेस की इस नापाक साजिश से भलीभांति अवगत है और वह गुजरात का अपमान करने वाली एवं गुजरात को विकास से महरूम रखने के लिए कांग्रेस को सजा देने का मन बना लिया है।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस यूपी में 16 नगर निगमों में से एक भी निगम चुनाव नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा कि 1995 के बाद हर बार कांग्रेस गुजरात में कहती है कि कांग्रेस आवे छे, आवे छे, आवे छे, लेकिन अमेठी और उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि कांग्रेस गई, कांग्रेस गई, कांग्रेस गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गुजरात में जीत का दिवास्वप्न आ रहा है, जबकि गुजरात की जनता ने हर बार कांग्रेस को उसकी नकारात्मक राजनीति का माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद से देश में हुए लगभग हर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, चाहे वह विधानसभा चुनाव हों या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू हुई विकास यात्रा पहले श्रीमती आनंदीबेन पटेल और अब श्री विजयभाई रुपाणी एवं श्री नितिनभाई पटेल जी के नेतृत्व में निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि 1995 के बाद से आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को सिर झुकाना पड़े। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज तक साढ़े तीन सालों में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश को भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी एवं

निर्णायक सरकार देने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जब भी हम चुनावों में जाते हैं तो हम पांच साल के पाई-पाई का और पल-पल का हिसाब देश और राज्य की जनता को देते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भी हम हर सभा में अपने कामों का हिसाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पहले इस बात का तो जवाब दे कि जब केंद्र में 10 वर्षों तक सोनिया-मनमोहन की सरकार थी, तब उन्होंने गुजरात के विकास के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि एक परिवार ने देश में 50 सालों तक शासन किया और कांग्रेस पार्टी अपने 50 सालों का हिसाब देने की बजाय हमसे साढ़े तीन साल का हिसाब मांग रहे हैं!

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुजरात में हर गांव तक 24 घंटे बिजली आई है, क़ानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और गुजरात को कर्फ्यू व हिंसा के मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि सौनी परियोजना के तहत नर्मदा परियोजना के जरिये कच्छ, सौराष्ट्र एवं राज्य के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जहां कांग्रेस के शासन में कभी पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि उलटे राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया और वर्तमान में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने गुजरात को पानी के लिए तरसाने का कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातियों में टकराव और भाई-भाई में झगड़े लगवाकर चुनाव में राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने डेयरी का पुनरुद्धार किया, जो आज सौराष्ट्र की आम जनता की जीविका का महत्वपूर्ण साधन है।

श्री शाह ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब 13वें वित्त आयोग के समय गुजरात को विकास के लिए केवल 63,346 करोड़ रुपए मिलते थे, आज जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब गुजरात को 14वें वित्त आयोग में 1,58,377 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं, जो 13वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय गुजरात का बजट केवल 10,000 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान में गुजरात का बजट 1,72,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 106 लोक-कल्याणकारी योजनायें शुरू की गई हैं और ये सभी योजनायें सर्व-स्पर्शी एवं सर्व-समावेशक हैं। योजनाओं के नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज माताओं को धुंए से मुक्ति मिली है, गांवों में बिजली पहुंची है, देश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, किसानों के लिए फसल बीमा लागू की गई है, आम जनता को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, दवाइयों के दाम कम हुए हैं और न जाने कितनी ही योजनायें देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक को मिल सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गांवों तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि कपास उत्पादन में लगभग 6 गुनी वृद्धि हुई, दूध का उत्पादन 6 गुना बढ़ा, साथ ही गन्ना, गेहूं, मूंगफली, सब्जी और फलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन साल में मोदी सरकार ने गुजरात को बुलेट ट्रेन की सौगात दी, 1200 किमी से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग देने का काम किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, एम्स दिया, आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिए ज्यादा फंड दिया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय आये दिन आतंकवादी हमले होते रहते थे, लेकिन मोदी सरकार में जब उरी में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे हुए सोये हुए वीर जवानों को कायराना हमले में शहीद कर दिया तो 10 ही दिन में मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सेना के जवानों के शौर्य के बल पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हमारे जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक की प्रशंसा हुई, लेकिन राहुल गांधी इसका प्रूफ मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा आजादी के नारे लगाए जाने और रोहिंग्या को भारत में शरण देने को लेकर कांग्रेस नेता कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वे अपने नेताओं के इस बयान से सहमत हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता कांग्रेस की नापाक हरकतों से भलीभांति परिचित है और वह आने वाले चुनावों में कांग्रेस को माकूल जवाब देगी।■

भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुजरात में हर गांव तक 24 घंटे बिजली आई है, क़ानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और गुजरात को कर्फ्यू व हिंसा के मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि सौनी परियोजना के तहत नर्मदा परियोजना के जरिये कच्छ, सौराष्ट्र एवं राज्य के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जहां कांग्रेस के शासन में कभी पानी नहीं पहुंचा था।

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत

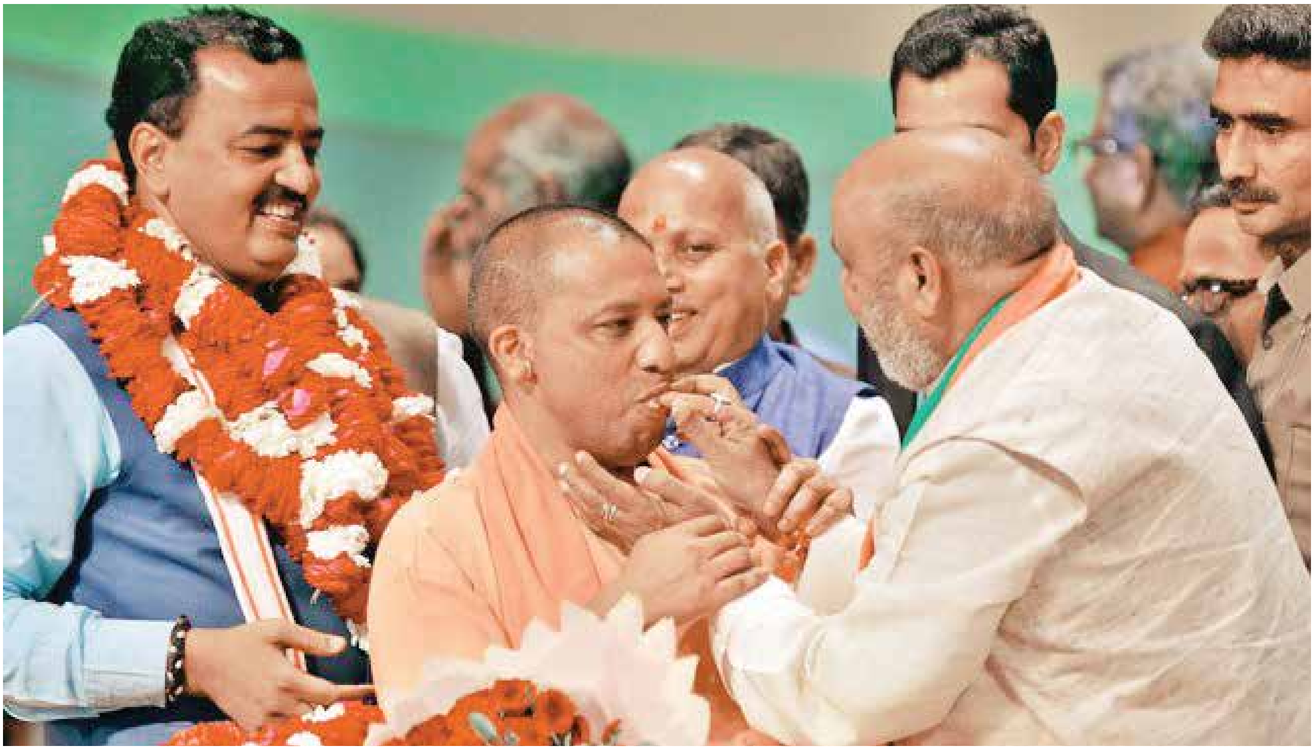

उत्तर प्रदेश के गत विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। प्रदेश के 16 नगर निगम, 198 नगरपालिका और 438 नगर पंचायतों के चुनाव के परिणाम 1 दिसंबर को आए। भाजपा ने 16 नगर निगमों में से 14 पर जीत का परचम लहराया। 2 पर बसपा को जीत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सूफड़ा-साफ हो गया। नगरपालिका और नगर पंचायतों में भी भाजपा आगे रही।

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में मिली भारी जीत के अवसर पर हुए उत्सव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने निकाय चुनाव में मिली अभूतपूर्व विजय को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण नीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के कुशल निर्देशन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनकल्याण की दिशा में किये जा रहे कार्यों की जीत बताया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल एवं समस्त पदाधिकारी, निकाय चुनाव की पूरी टीम सभी प्रभारी एवं कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

डॉ. पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश की जनता ने केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों और एक सुरक्षित समाज व भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाती है। यह जीत हमें जनकल्याण की दिशा में और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगी। डॉ. पाण्डेय ने चुनावों में विजयी सभी मेयर, चेयरमैन व पार्षदों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

उत्तर प्रदेश नगर निगम में विजयी भाजपा महापौरों की सूची

आगरा	नवीन कुमार जैन
कानपुर नगर	प्रमिला पांडेय
झांसी	रामतीर्थ सिंघल
वाराणसी	मृदुला जायसवाल
इलाहाबाद	अभिलाषा गुप्ता
गोरखपुर	सीताराम जायसवाल
लखनऊ	संयुक्ता भाटिया
मथुरा	मुकेश
फिरोजाबाद	नूतन राठौर
गाजियाबाद	आशा शर्मा
सहारनपुर	संजीव वालिया
बरेली	उमेश गौतम
मुरादाबाद	विनोद अग्रवाल
अयोध्या	ऋषिकेश जायसवाल

विकास की इस देश में फिर एक बार जीत हुई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में भव्य जीत के लिए प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। यह जीत हमें जन कल्याण की दिशा में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह जीत हर प्रदेशवासी की पीएम मोदी के केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा की प्रदेश सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और विकासशील शासन में अटूट विश्वास की जीत है। मैं प्रदेश की जनता को भाजपा में निरंतर विश्वास प्रकट कर विजयश्री प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

— अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

अपने सम्बोधन में कहा कि यह विजय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी में जनता का अटूट विश्वास और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का कुशल नेतृत्व प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बसंल के कुशल प्रबन्धन में एवं प्रदेश पदाधिकारी तथा मेरे मत्रिमण्डल के सभी सहयोगी तथा भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम का परिणाम है। हम विकास के पथ पर अनवरत कार्य करते रहेंगे। यह प्रदेश की लोक कल्याणकारी नीतियों और विकासशील शासन में अटूट विश्वास की जीत है। यह जीत भाजपा की विकास एवं सुशासन की प्रति गहरी प्रतिबद्धता की जीत है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर वो लोग जो गुजरात के चुनाव के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उनका नगर निकायों में खाता भी नहीं खुल पाया है और अमेठी में भी उनका सूपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार प्रधानमंत्री जी को फिर से अपना समर्थन दिया है। देश के ढांचागत सुधार और आम जनता तक जनसुविधाओं को पहुंचाने में किये जा रहे है 3.5 वर्षों के प्रयास पर अपनी मोहर लगाई है। लगभग 125 लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, यह सामूहिक प्रयास का परिणाम हैं।

उन्होंने कहा कि मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल, प्रदेश पदाधिकारी, मंत्रिमण्डल के सभी सहयोगियों को और सभी विजयी श्री प्राप्त किये सभी भाजपा के प्रत्याशियों समेत नगर प्रमुख सभी चेयरमैन और जीते हुए सभी सभासदों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर प्रदेश के 4.5 करोड़ मतदाताओं का जिन्होंने अपनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित की तथा इस अवसर पर मीडिया का भी आभार व्यक्त करूंगा ।

भाजपा महापौरों ने प्रधानमंत्री से की भेंट

उत्तर प्रदेश में भाजपा के 14 नवनिर्वाचित महापौरों ने 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति खासतौर पर नगर निगम के दायित्व के रूप में स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री के साथ भाजपा महापौरों की इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों का विकास के माध्यम से कायाकल्प करने में जन-भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत को लेकर जनता का आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, दोनों नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और दैनिक सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसे नगर नियोजन के लिए कटिबद्ध हैं।

उत्तर प्रदेश से भाजपा के नव निर्वाचित 14 नगर निगमों के महापौरों एवं अमेठी नगर पंचायत एवं अमेठी जिले की जायस

नगरपालिका परिषद, के अध्यक्ष की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात प्रधानमंत्री-निवास पर हुई। मथुरा के नवनिर्वाचित महापौर मुकेश आर्यबंधु ने कहा कि प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात काफी अच्छी और प्रेरणादायक रही। उन्होंने स्वच्छता के महत्व को बताया और हमसे कहा कि नगर निगम का दायित्व स्वच्छता से काफी गहराई से जुड़ा होता है, ऐसे में नगरों को साफ रखने के लिये संकल्पित होकर काम करें। ■

जीवेम् शरदः शतम्

जन्मदिन : 25 दिसंबर

पूर्व प्रधानमंत्री

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी

के जन्मदिन पर कमल संदेश परिवार उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता है।

राष्ट्रपति ने दी दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी

भारत के राष्ट्रपति ने 23 नवंबर को दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश का उद्देश्य अवांछनीय एवं बेईमान लोगों को उपर्युक्त संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग करने अथवा उन्हें निष्प्रभावी बनाने से रोकने के लिए आवश्यक हिफाजती इंतजाम करना है। संशोधनों का उद्देश्य उन लोगों को इसके दायरे से बाहर रखना है, जिन्होंने जानबूझकर डिफॉल्ट किया है अथवा जो फंसे कर्जों (एनपीए) से संबंधित हैं और जिन्हें नियमों का अनुपालन न करने की आदत है और इस तरह जिन्हें किसी कंपनी के दिवाला संबंधी विवादों के सफल समाधान में बाधक माना जाता है। इस तरह के विवाद समाधान अथवा परिसमापन प्रक्रिया में भाग लेने से इस तरह के लोगों को प्रतिबंधित करने के अलावा उपर्युक्त संशोधन में इस तरह की रोकथाम के लिए यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि ऋणदाताओं की समिति मंजूरी देने से पहले विवाद समाधान योजना की लाभप्रदता एवं संभाव्यता सुनिश्चित करेगी। भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को भी अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि आईबीबीआई के नियम-कायदों को भी हाल ही में संशोधित किया गया है, ताकि विवाद समाधान पेश करने वाले आवेदक के पूर्ववर्ती से संबंधित सूचनाओं के साथ-साथ वरीयता, कम मूल्यांकन या धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन के बारे में भी जानकारियां ऋणदाताओं की समिति के समक्ष पेश की जा सकें, जिससे कि वह समुचित जानकारी के आधार पर इस बारे में उपयुक्त निर्णय ले सके।

बेहतर अनुपालन के लिए अन्य कदम उठाने के अलावा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और समाधान प्रक्रिया से अवांछनीय तत्वों को बाहर रखना भी सरकार के मौजूदा सुधारों का एक हिस्सा है। इसी तरह धनराशि के अन्यत्र उपयोग के लिए कॉरपोरेट ढांचे का दुरुपयोग रोकने हेतु डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार मौजूदा सुधार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ईमानदार कारोबारियों एवं उभरते उद्यमियों को विश्वसनीय एवं स्थिर नियामकीय माहौल में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त अध्यादेश के जरिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 2, 5, 25, 30, 35 एवं 240 में संशोधन किए गए हैं और इसके साथ ही संहिता में 29ए तथा 235ए नामक नई धाराएं जोड़ी गई हैं।

संशोधनों का सार निम्न हैः

1. संहिता की धारा 2 के अनुच्छेद (ई) को तीन अनुच्छेदों ने प्रतिस्थापित किया है। इससे व्यक्तियों एवं भागीदारी कंपनियों से संबंधित संहिता के भाग III को विभिन्न चरणों में शुरू करने में मदद मिलेगी।

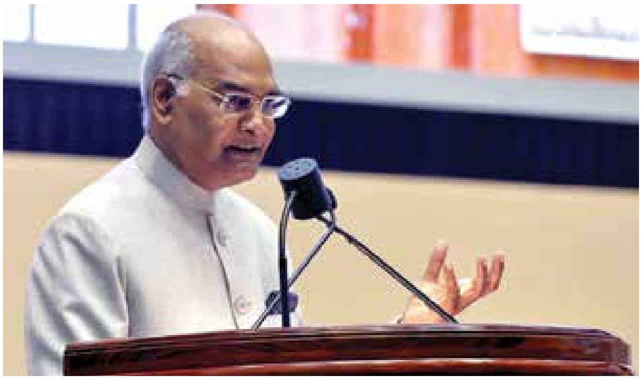

2. संहिता की धारा 5 के अनुच्छेद (25) एवं (26), जो 'समाधान संबंधी आवेदक' को परिभाषित करते हैं, में संशोधन किया गया है, ताकि इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3. संहिता की धारा 25(2)(एच) में संशोधन किया गया है, ताकि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से मंजूरी मिलने के बाद समाधान संबंधी प्रोफेशनल अर्हता की शर्तें निर्दिष्ट कर सके और इसके साथ ही कॉरपोरेट कर्जदार के कारोबार के परिचालन स्तर एवं इसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजनाएं आमंत्रित की जा सकें।

4. धारा 29ए एक नई धारा है जिसके जरिए कुछ विशेष व्यक्तियों को समाधान आवेदक बनने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे लोग जिन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

क- जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले व्यक्ति या कंपनी

ख- ऐसे लोग या कंपनी जिनके खातों को एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और जो ब्याज सहित अपनी बकाया राशि तथा समाधान योजना पेश करने से पहले खाते से संबंधित प्रभार का निपटान करने में असमर्थ हैं।

ग- ऐसे लोग या निकाय जिन्होंने इस संहिता के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहे किसी कॉरपोरेट कर्जदार के संबंध में किसी ऋणदाता को कार्यान्वयन योग्य गारंटी दे रखी है।

घ- उपर्युक्त लोगों या निकायों से संबंधित ऐसे व्यक्ति जो प्रमोटर हैं या प्रस्ताव पेश करने वाले आवेदक के नियंत्रण वाले प्रबंधन में

हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान कॉरपोरेट कर्जदार के नियंत्रण वाले प्रबंधन में शामिल होने वाले हैं।

5. यह भी प्रावधान किया गया है कि सीओसी ऐसी किसी भी समाधान योजना को नामंजूर कर देगी जिसे अध्यादेश जारी होने से पहले पेश किया गया है, लेकिन जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। सीओसी ऐसे आवेदक द्वारा पेश की गई समाधान योजना को भी अस्वीकृत कर देगी जिसे नई धारा 29ए के तहत अयोग्य करार दिया गया है। ऐसे सभी मामलों जिनमें नामंजूर करने के कारण सीओसी के विचारार्थ कोई भी योजना उपलब्ध नहीं रहेगी, तो वैसी स्थिति में समिति नई समाधान योजनाओं को आमंत्रित कर सकती है।

6. धारा 30(4) में संशोधन किया गया है ताकि सीओसी अपनी मंजूरी देने से पहले आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अलावा किसी समाधान योजना की संभाव्यता एवं लाभप्रदता पर विचार करने के लिए बाध्य होगी।

7. ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की बिक्री पर धारा 35(1)(एफ) में संशोधन के जरिए रोक लगा दी गई है, जिन्हें धारा 29ए के तहत कोई भी समाधान योजना पेश करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

8. संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ निर्धारित नियम-कायदों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नई धारा 235ए के तहत ऐसे मामलों में संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिनमें किसी विशेष पेनाल्टी या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। जुर्माना राशि अच्छी-खासी होगी, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगी और जिसे बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा सकता है।

9. संहिता की धारा 240, जिसमें आईबीबीआई द्वारा नियम-कायदे बनाने का अधिकार दिया गया है, में अनुवर्ती संशोधन किए गए हैं, ताकि धारा 25(2)(एच) और धारा 30(4) के तहत अधिकारों का नियमन किया जा सके। ■

दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.3 प्रतिशत

साल 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 6.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा जुलाई से सितंबर का है। पहली तिमाही में यह दर 5.7 प्रतिशत थी। इस वृद्धि से संकेत मिलता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के असर से उबर रही है। इससे यह भी पता चलता है कि जीएसटी के सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की हालत और सुधर सकती है, जिससे विकास के साथ-साथ रोजगार में भी इजाफा होगा।

वास्तविक जीवीए वृद्धि में भी अच्छी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जो पहली तिमाही के 5.6 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 6.1 प्रतिशत तक जा पहुंची है। यह बढ़ोत्तरी कृषि वृद्धि दर के पहली तिमाही के 2.3 प्रतिशत के मुकाबले दूसरी तिमाही में गिरकर 1.7 प्रतिशत पर आ जाने के बावजूद दर्ज की गई है।

जुलाई-सितंबर के दौरान ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली उत्पादन में अच्छी रिकवरी हुई है। सितंबर तिमाही में 6 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों में 'विनिर्माण', 'बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं' और 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं' शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से समग्र विकास दर में देखी जा गिरावट की प्रवृत्ति अब पूरी तरह बदल चुकी है। श्री जेटली ने यह भी कहा कि इस तिमाही में वृद्धि दर में तेजी को विनिर्माण में तेज बढ़ोतरी से सहायता मिली है, जो पहली तिमाही के 1.2 प्रतिशत के मुकाबले दूसरी तिमाही के दौरान 7 प्रतिशत तक पहुंच गई। दूसरी तिमाही के दौरान, बिजली एवं अन्य यूटिलिटिज 7.6 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी, व्यापार,

ट्रांसपोर्टेशन एवं संचार में 9.9 प्रतिशत के इजाफे से भी इस बढ़ोतरी में मदद मिली। कुल मिलाकर, दूसरी तिमाही के दौरान, सेवा क्षेत्र ने 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई।

वित्त मंत्री ने कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था इस वर्ष के प्रारंभ में आए रूपांतरकारी बदलावों के दौर का मजबूती से मुकाबला कर आगे बढ़ चुकी है और निकट भविष्य में इसमें स्थायी सुधार आना तय है।

मुख्य सांख्यिकीविद् टीसीए अनंत ने कहा कि पांच तिमाहियों में गिरावट के बाद जीडीपी में तेजी दिखी है, जो काफी सकारात्मक है। सबसे ज्यादा 7 प्रतिशत उछाल मैन्युफैक्चरिंग में रहा। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 9.9 प्रतिशत की तेजी से बढ़े। ■

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत को मिली बड़ी कामयाबी

दूसरी बार जज चुने गए दलवीर भंडारी

भारत के श्री दलवीर भंडारी को नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिर से जज के तौर पर चुन लिया गया। जस्टिस दलवीर भंडारी को जनरल एसेंबली में 183 मत मिले, वहीं सुरक्षा परिषद में जस्टिस भंडारी को सभी 15 मत मिले। श्री भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के उम्मीदवार श्री क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था, लेकिन आखिरी क्षणों में ब्रिटेन ने अपने उम्मीदवार को चुनाव से हटा लिया। गौरतलब है कि वर्ष 1945 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा पहली बार हुआ, जब इसमें कोई ब्रिटिश न्यायाधीश नहीं होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को उन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पुनः निर्वाचित होने पर अपनी बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा, 'मैं न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पुनः निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और विदेश मंत्रालय एवं राजनयिक मिशनों में कार्यरत उनकी संपूर्ण टीम को उनके अनथक प्रयासों के लिए बधाई, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायमूर्ति का पुनर्निर्वाचन हो सका। हम संयुक्त राष्ट महासभा के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने भारत के प्रति अपना समर्थन और विश्वास प्रकट किया है।' जस्टिस भंडारी की जीत पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, 'वंदे मातरम- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की जीत हुई। जय हिंद'। ■

शहरी गरीबों के लिये पीएमएवाई के तहत 1,12,083 किफायती आवास अनुमोदित

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई/शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिये 1,681 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 8,105 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1,12,083 अतिरिक्त किफायती आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी 29 नवंबर को आयोजित केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 28वीं बैठक में दी गई। मध्य प्रदेश के लिए 520 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 3080 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 25 शहरों और कस्बों में 34,680 आवासों के निर्माण, हरियाणा के लिए 363 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 1,721 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 28 शहरों और कस्बों में 24,221 आवासों, महाराष्ट्र के लिए 173 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 860 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 11,523 आवासों के निर्माण, झारखंड के लिए 427 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 2080 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5 शहरों और कस्बों में 28,477 आवासों, केरल के लिए 147 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 295 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 49 शहरों और कस्बों में 9836 आवासों, मिजोरम के लिए 49 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 65 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 7 शहरों और कस्बों में 3,270 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 44,692 नए आवासों के निर्माण, बीएलसी के तहत हरियाणा में 1857 आवासों में सुधार और भागीदारी किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत झारखंड में 28477, हरियाणा में 13946 नए आवासों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई।

बीएलसी घटक के तहत मध्य प्रदेश में 16,104 नए आवास, केरल में 9836 आवास, महाराष्ट्र में 5131 आवास, मिजोरम में 3270 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बीएलसी के तहत पात्र लाभार्थी को उसके मालिकाना हक की भूमि पर आवास निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। उपरोक्त प्रस्ताविक आवासों के साथ सीएसएमसी की अंतिम मंजूरी के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत कुल आवासों की संख्या 30,52,828 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आरएवाई योजना की परियोजनाओं को शामिल करने के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत वित्त पोषित कुल आवासों की संख्या 31,94,676 होगी। ■

भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था

| दीनदयाल उपाध्याय |

राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने अर्थ का है। सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके आर्थिक पहलू पर भी विचार करें। हमारे आर्थिक मूल्य क्या हैं और जीवन के किन मूल्यों के आधार पर हम समाज को सुख, श्री और समृद्धि से संपन्न कर सकते हैं- इन प्रश्नों पर भी विचार करना अवश्यक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे आर्थिक और भौतिक जीवन के विकास की भी समुचित व्यवस्था की गई है। जो यह बात सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति तो केवल अध्यात्मवाद पर ही जोर देती है तथा भौतिक उन्नति को उसमें कोई स्थान नहीं, उनकी यह धारणा बिल्कुल ही निर्मूल है। भारतीय संस्कृति में भौतिक विकास के लिए उतना ही स्थान है, जितना आध्यात्मिक विकास के लिए। हमारे अपने आर्थिक मूल्य हैं; अपनी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था का देश और काल दोनों से ही संबंध है। इसलिए हमारे यहां युगधर्म और राष्ट्रधर्म दोनों की बात स्पष्ट रूप से कही गई है।

राष्ट्रधर्म

आज युग की दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे भौतिक साधनों का भी विकास हुआ है। अतरराष्ट्रीय समानता की बात भी हम कहते हैं। परंतु तथ्य फिर भी कुछ और है। प्रत्येक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। वे अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही विचार करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक और भौतिक साधन भी भिन्न-भिन्न हैं। अतः हम अंतरराष्ट्रीय समानता के आधार पर युगधर्म की बात कहकर राष्ट्रधर्म को भुला नहीं सकते।

मानसिक वृत्तियां और आर्थिक प्रयत्न

एक बात और, आर्थिक पहलू पर विचार करते समय लोग मानसिक प्रवृत्तियों पर विचार नहीं करते, जबकि हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर मानसिक प्रवृत्तियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रवृत्तियां सांस्कृतिक जीवन से प्रभावित होती हैं। अतः हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव रहता है। हमारी संस्कृति में भी हमारे आर्थिक प्रयास किस आधार पर चलें, इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है; भौतिक विकास के लिए उसमें समुचित स्थान है।

आर्थिक विकास को स्थान

हमारे धर्म में पग-पग पर इहलोक और परलोक बनाने की बात कही गई है। इसलिए हमने लक्ष्मी को देवी स्वरूपा माना है, उसमें देवत्व की स्थापना की है। इसलिए हम उसे काम्य और भोग्य भाव से न देखकर पूज्य और श्रद्धा भाव से देखते हैं। 'वंदेमातरम्' में भी जब हम

भारतमाता की वंदना करते हैं, सबसे पहले उसका 'सुजलां, सुफलां, मलयज शीतलाम्' वाला रूप ही हमारे सामने आता है, अर्थात् (प्रथम हम उसकी भौतिक श्रीसमृद्धि का ही विचार करते हैं, उसके अन्य रूपों की कल्पना तो बाद में ही की जाती है। अतः भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' की बात कहकर हम यह तो कह ही नहीं सकते कि इस संस्कृति में केवल अध्यात्म और ब्रह्म पर ही विचार किया जाता है तथा मौलिक विकास को पूर्ण रूप से उपेक्षित किया जाता है। अब जब भौतिक विकास की बात को हमारी संस्कृति प्रतिपादित करती है तो उसके लिए उसकी समुचित व्यवस्था भी की गई है। हमारा अपना एक आर्थिक दर्शन है, उसके आधार पर हमारे मनीषियों ने आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन व्यवस्थाओं में भिन्नता मिल सकती है, क्योंकि मनु महाराज ने यदि अभिनवीकरण का बहिष्कार किया है तो कौटिल्य ने उसका प्रतिपादन, परंतु दोनों का दर्शन फिर भी एक है। अतः हम उसके व्यावहारिक पहलू पर विचार न कर दार्शनिक पहलू पर ही विचार करें। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए जैसा कि पूर्व भी कहा जा चुका है, हमारे यहां युगधर्म और राष्ट्रधर्म दोनों की अलग-अलग बात कही गई है, अर्थात् युग और देश की परिस्थिति के अनुसार ही हम अपनी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करें।

संपत्ति का अधिकार

अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह उठता है कि समाज में संपत्ति पर किसका अधिकार हो। कुछ लोग यह नारा लगाते हैं कि 'कमाने वाला खाएगा'। एक दृष्टि यह ठीक भी है, क्योंकि यह मनुष्य की प्रकृति है। अर्थशास्त्र इसी का प्रतिपादन करता है। परंतु मानव और समाज कल्याण के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्वयं

कर्म करके, उसके फल को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक दूसरे को अर्पण कर देने के भाव का आदर्श भी आवश्यक है। यही संस्कृति है, परंतु इस प्रकार की संस्कृति आज व्यवहार में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती और प्रकृति का केवल नारा भर लगाया जाता है। व्यवहार में आज इन दोनों से भिन्न एक तीसरी चीज़ ही सामने है-विकृति अर्थात् कर्म तो कोई करे कमाए कोई, और खाए कोई अन्य। यह ज़बरदस्ती ही आज चारों ओर दिखाई देती है। यही विकृति है। परंतु भारतीय संस्कृति प्रकृति से भी ऊपर उस परम आदर्श पर बल देती है, जिसको गीता के कर्म के सिद्धांत में व्यक्त किया गया है-अर्थात् फल की भावना से रहित होकर कर्म करो और उससे अर्जित फल को भगवतार्पण कर दो। भगवान् अर्थात् समाज। ईश्वर का प्रत्यक्ष और विराट् स्वरूप आज समाज ही है। वही विराट् पुरुष है-यही मानकर हम चलें और अपने समस्त कर्मो के फल हम समाज को अर्पण कर दें।

हमारी समाज कल्पना

अब जब समाज की बात उठती है तो उसके विषय में भी हमारी कल्पना स्पष्ट हो जानी आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के अनुसार समाज के बहुत से रूप हैं। रूस के अनुसार उसका 'स्टेट' रूप में कभी प्रयोग नहीं होता और न उसमें रूस की विचारधारा के अनुसार राष्ट्रीयकरण को ही महत्त्व दिया जाता है। भारतीय समाज रचना में व्यक्ति अर्थात् व्यष्टि को प्रमुख स्थान दिया गया है। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। हम समाज में व्यक्ति और परिवार से लेकर ग्राम, राष्ट्र और अखिल विश्व तक की कल्पना करते हैं। इसलिए जो कुछ हम उत्पन्न करें, उसे संपूर्ण राष्ट्र के हित में व्यय कर दें। राष्ट्र ही हमारे कर्म की प्रेरणा का स्रोत रहे। यही भावना भारतीय संस्कृति के आर्थिक रूप का मूल आधार है। इसी आधार पर हम समाज को सुख, श्री और समृद्धि से संपन्न बना सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम भारतवर्ष को कर्मभूमि मानकर चलें, भोगभूमि नहीं। जहां भोग की भावना आ जाती है, वहां परिश्रम और कर्म चाहे स्वयं ही क्यों न किया जाए एक पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण हो जाता है, वह हमें मान्य नहीं, क्योंकि 'प्रकृति' होते हुए भी वहां 'जंगल का क़ानून' होता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रधान होता है तथा समाज और राष्ट्र का सामूहिक हित गौण पड़ जाता है। वहां फिर ठीक वितरण नहीं हो पाता और समाज के सामूहिक विकास का मार्ग सिमटकर कुछ लोगों की पकड़ में चला जाता है। अतः राष्ट्र की चिंता को प्रधान मानकर हम अपनी 'प्रकृत' अवस्था से भी ऊपर उठकर 'संस्कृत' अवस्था को प्राप्त हों। जहां त्याग ही सब कुछ है और उसी में परम आनंद है। व्यावहारिक रूप में यदि हम इस प्रकार न्यूनतम वेतन कल्पना लेकर चलें तो फिर हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कर्म का परिश्रम यदि हम समाज को अर्पण कर देंगे तो हमारी चिंता कौन करेगा। तब समाज हमारी चिंता करेगा, क्योंकि हम समाज के अंग हैं और समाज का जब सामूहिक विकास होगा तो कोई कारण नहीं कि हमारा विकास न हो। ■

(पांचजन्य, अक्तूबर २१, 1957)

भारतीय वायुसेना की हवा से हवा में ईंधन भरने में असाधारण उपलब्धि

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने आसमान में त्वरित चेतावनी और नियंत्रण (एईडब्ल्यू एंड सी) कार्य करने वाले एमब्रियर परिवहन विमान में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक अवधि के लिए उड़ान भरने के वास्ते हवा से हवा में ईंधन भरने (एएआर) में सफलता हासिल की है। एमब्रियर प्लेटफार्म पर पहली बार हवा से हवा में ईंधन भरा गया है।

भारतीय वायु सेना के पायलटों द्वारा किए गए हवा में ही तलाश कर लंगर डालना यानी "प्रोब और ड्रोग" एएआर पद्धति में असाधारण उड़ान कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईंधन देने वाले विमान को ईंधन भरने वाले विमान के टैंकर के पीछे की टोकरीनुमा संरचना को तलाश कर उसमें सटीक तरीके से ईंधन डालना होता है। एएआर की प्रक्रिया के दौरान दोनों ही विमानों में सटीक उड़ान मानदंड कायम रखे जाते हैं। ऐसी क्षमता वाली दुनिया की कुछ वायु सेना में से एक भारतीय वायु सेना है। हवा में उड़ान भरते हुए केवल 10 मिनट ईंधन भरने से विमान अतिरिक्त 4 घंटे उड़ान भर सकता है। इस उपलब्धि से भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता को काफी बढ़ावा मिला है।

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय

(25 दिसम्बर, 1861– 12 नवम्बर, 1946)

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान् स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् और बड़े समाज सुधारक थे। 'महामना' मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मन्दिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के ख़िलाफ़ देश भर में आंदोलन चलाया। पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया।

इलाहाबाद में 25 दिसम्बर, 1861 में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान् कार्यों के चलते 'महामना' कहलाये। इनके पिता का नाम ब्रजनाथ और माता का नाम भूनादेवी था। चूंकि ये लोग मालवा के मूल निवासी थे, इसीलिए मालवीय कहलाए। महामना मालवीय जी ने सन् 1884 में उच्च शिक्षा समाप्त की। शिक्षा समाप्त करते ही उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया, पर जब कभी अवसर मिलता वे किसी पत्र इत्यादि के लिये लेखादि लिखते। 1885 ई. में वे एक स्कूल में अध्यापक हो गये, परन्तु शीघ्र ही वक़ालत का पेशा अपना कर 1893 ई. में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वक़ील के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और 1885 तथा 1907 ई. के बीच तीन पत्रों- हिन्दुस्तान, इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय का सम्पादन किया।

मदन मोहन मालवीय की प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद के श्री धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में हुई। इसके बाद मालवीयजी ने 1879 में इलाहाबाद ज़िला स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और म्योर सेंट्रल कॉलेज से एफ.ए. की। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मदन मोहन को कभी-कभी फ़ीस के भी लाले पड़ जाते थे। इस आर्थिक विपन्नता के कारण बी.ए. करने के बाद ही मालवीयजी ने एक सरकारी विद्यालय में 40 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापकी शुरू कर दी।

मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिन्दी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्मक्षेत्र में पदार्पण किया। वास्तव में मालवीय जी ने पत्रों को हिन्दी-प्रचार का प्रमुख साधन बना लिया। हिन्दी आन्दोलन के सर्वप्रथम नेता होने के कारण मालवीय जी पर हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि का दायित्व भी आ गया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन् 1910 ई. में उनकी सहायता से इलाहाबाद में 'अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की स्थापना हुई। उसी वर्ष अक्टूबर में सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके सभापति मालवीय जी थे। महामना मालवीय जी अपने युग के प्रधान नेताओं में थे। जिन्होंने हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान को सर्वोच्च स्थान पर प्रस्थापित कराया।

मालवीय ने असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का ज़बर्दस्त विरोध किया और इसके ख़िलाफ़ देश भर में जनजागरण अभियान भी चलाया। महामना तुष्टीकरण की नीतियों के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। वह देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया।

पं. मदन मोहन मालवीय जी कई संस्थाओं के संस्थापक तथा कई पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। इस रूप में वे हिन्दू आदर्शों, सनातन धर्म तथा संस्कारों के पालन द्वारा राष्ट्र-निर्माण की पहल की। इस दिशा में 'प्रयाग हिन्दू सभा' की स्थापना कर समसामयिक समस्याओं के संबंध में विचार व्यक्त करते रहे। सन् 1884 ई. में वे हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सन् 1885 ई. में 'इण्डियन यूनियन' का सम्पादन, सन् 1887 ई. में 'भारत-धर्म महामण्डल' की स्थापना कर सनातन धर्म के प्रचार का कार्य किया।

सन् 1889 ई. में 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन, 1891 ई. में 'इण्डियन ओपीनियन' का सम्पादन कर उन्होंने पत्रकारिता को नई दिशा दी। इसके साथ ही सन् 1891 ई. में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण व विशिष्ट मामलों में अपना लोहा मनवाया। सन् 1913 ई. में वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया, ताकि राष्ट्र को स्वाधीन देख सकें। मालवीय जी ने सन् 1916 ई. में 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की। वास्तव में यह महान कार्य शिक्षा और साहित्य सेवा का अमिट शिलालेख है। मालवीय जी आजीवन देश सेवा में लगे रहे और 12 नवम्बर, 1946 ई. को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। ■

पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने की अफवाह

पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे बकाएदारों के सम्बंध में कड़े फैसले लेने की बजाय बैंकों द्वारा कर्ज वर्गीकरण में राहत देते हुए ऐसे बकाएदारों को नॉन-एनपीए खाताधारक बनाए रखा गया। इससे इन कर्जों का पुनर्गठन हो गया और बैंकों का नुकसान छिपा रह गया। बैंक ऐसे कर्जदारों को लगातार कर्ज देते रहे और यह प्रक्रिया चलती रही। वर्तमान सरकार ने इस गठजोड़ को पहचाना और बकाएदारों के लिए कड़े फैसले लिए।

| अरूण जेटली |

पिछले कुछ दिनों से बैंकों द्वारा पूंजीपतियों का कर्ज माफ किये जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। अब समय आ गया है कि देश को इस सम्बंध में सही तथ्यों का पता चलना चाहिए। साल 2008 से 2014 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बेहिसाब पैसा कर्ज के रूप में कई उद्योगों को बांटा। जनता को उन अफवाह फैलाने वालों से पूछना चाहिए कि किसके कहने पर या किसके दबाव में इतना कर्ज बांटा गया। उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब इन कर्ज लेने वालों ने अपने कर्ज और ब्याज के भुगतान में देरी की तो उस समय की सरकार ने क्या कदम उठाए।

उस समय की सरकार ने ऐसे बकाएदारों के सम्बंध में कड़े फैसले लेने की बजाय बैंकों द्वारा कर्ज वर्गीकरण में राहत देते हुए ऐसे बकाएदारों को नॉन-एनपीए खाताधारक बनाए रखा गया। इससे इन कर्जों का पुनर्गठन हो गया और बैंकों का नुकसान छिपा रह गया। बैंक ऐसे कर्जदारों को लगातार कर्ज देते रहे और यह प्रक्रिया चलती रही। वर्तमान सरकार ने इस गठजोड़ को पहचाना और बकाएदारों के लिए कड़े फैसले लिए। इनसोल्वेन्सी एंड बैंकरप्टसी कोड़ लागू किया गया और इसमें संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जिन कम्पनियों का पैसा बैंकों को वापस नहीं किया गया, उनसे सम्बंधित देनदारों को ऐसी कंपनियों के कारोबार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बैंकों को आवश्यक पूंजी भी मुहैया कराई गई, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मज़बूत हो सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। बैंकों को पूंजी देने के पीछे कारण यह था कि ये बैंक मजबूर नहीं मज़बूत बन सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इससे पहले भी पूंजी मुहैया कराई गई हैं। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी सरकार ने पुनर्पूंजीकरण के लिए बैंकों को 44,000 करोड़ रुपए दिए थे। क्या वह भी पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने के लिए थे?

आक्रामक उधार की विरासत:

2008 से 2014 के बीच आक्रामक उधार की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल अग्रिम लगभग 34,00,000 करोड़ रुपये बढ़े थे। इन पर भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा था, इसके बावजूद बैंकों ने ऋण वर्गीकरण में राहत देते हुए बकाएदारों

को नॉन-एनपीए खाताधारक बनाए रखा। इसके द्वारा बैंकों को हुए नुकसान और उनकी अनिश्चित स्थिति को दबाकर रखा गया।

एनपीए की पारदर्शी और वास्तविक पहचान करना:

पूर्ण रूप से प्रावधानों के अनुरूप और सही बैलेंसशीट्स के लिए 2015 में संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में एनपीए का खुलासा हुआ। एनपीए की सही पहचान होने से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की एनपीए रकम मार्च 2015 के 2,78,000 करोड़ से बढ़कर जून 2017 में 7,33,000 करोड़ हो गई। इसका मतलब है कि संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा के तहत गहन जांच में करीब 4,54,466 करोड़ रुपये के ऐसे कर्ज का पता चला, जो असल में एनपीए की श्रेणी में रखे जाने चाहिए थे और जिन्हें दबाकर रखा गया था।

अपेक्षित नुकसान के लिए प्रावधान:

पहले पुनर्गठित कर्जों के लिए उपलब्ध राहत के तहत लंबित ऋणों से होने वाले संभावित नुकसान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं बनाए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सफाई और एनपीए की पहचान करने की पहल की और अपेक्षित नुकसान के लिए अग्रिम प्रावधान बनाया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 1,80,000 करोड़ रुपये पूंजी की परिकल्पना की है। इसी के आधार पर सरकार ने

70,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। बड़ी संख्या में एनपीए और परिणामपरक प्रावधानों की जरूरत के बावजूद इंद्रधनुष के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक बैंक बेसल III मानदंडों का पालन करने में सफल रहे। 2013-14 और वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के बीच अपेक्षित नुकसान के लिए 3,79,080 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गए, जबकि उससे पहले के 10 सालों में 1,96,937 करोड़ रुपये के ही प्रावधान हुए थे।

कोई कर्जमाफी नहीं:

सरकार ने किसी भी बड़े एनपीए बकाएदार का कर्ज माफ नहीं किया है। इसके उलट, सरकार द्वारा लाए गए नए इनसोल्वेन्सी एंड बैंकरप्टसी कोड़ के तहत, 1,75,000 करोड़ रूपए के एनपीए के मामलों में 12 बड़े बकाएदारों से 6 से 9 महीनों में समय पर रिकवरी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मामले दर्ज कराए गए हैं। इन बड़े बकाएदारों की संपत्ति से एनपीए बकाया की रिकवरी करने के लिए चल रहे मामले अलग-अलग चरणों में हैं।

जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर शिकंजा:

बेईमान और अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए, एक अध्यादेश के जरिये, सरकार ने एनपीए खातों से जुड़े व्यक्तियों के एनसीएलटी में चल रही प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कदमों के द्वारा, देश में पहली बार, सरकार ने एक साफ और प्रभावी प्रणाली लागू की है। इसके द्वारा जानबूझकर बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले बकाएदारों को उनके व्यवसाय के प्रबंधन और उनसे प्रभावित होने वाली समयबद्ध रिकवरी से दूर रखा जा सकेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अभूतपूर्व पूंजीकरण:

क्रेडिट ऑफ-टेक में वृद्धि और नौकरियों का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण का निर्णय लिया है। इसके तहत, चालू वर्ष में अधिकतम आवंटन के साथ, अगले दो वित्त वर्षों के भीतर 2,11,000 करोड़ रुपये की पूंजि वृद्धि प्रभावित होगी। यह पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड्स के 1,35,000 करोड़ रुपये, बजट प्रावधान के 18,139 करोड़ रुपये, पूंजी को बढ़ाने और सरकारी शेयरहोल्डिंग को कम करने के कारण बाजार से आने वाले लगभग 58,000 करोड़ रुपये के बकाया के जरिये इसका बंदोबस्त किया जाएगा। पूंजी लगाने के माध्यम से एनपीए के कारण कमजोर हुए बैंक मजबूत बनेंगे और बाजार से पर्याप्त पूंजी बढ़ाने में सक्षम होंगे। यह पूंजि प्राप्त करने के लिए बैंकों को कई सुधार करने होंगे, ताकि दोबारा ऐसी स्थितियां न आएं।

ईमानदार व्यवसायियों को ऋण:

पिछले तीन सालों में उठाए गए इन मजबूत कदमों के माध्यम से न केवल विरासत में मिली समस्याएं हल हुई हैं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ताकत के पुनर्निमाण के लिए किए जा रहे सुधारों को भी बल मिला है। मजबूत और बड़े बैंकों के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के एकीकरण से शुरू हुई प्रक्रिया को यह घोषित पुनर्पूंजीकरण और आगे बढ़ाएगा। जहां ईमानदार व्यवसायी मजबूत और सुधरे हुए बैंकों से ऋण ले सकेंगे वहीं सख्त और साफ कानून तथा सरकार के चौतरफा सफाई अभियान के परिणाम स्वरूप देश में एक साफ-सुथरी प्रणाली विकसित होगी। ■

— लेखक केंद्रीय वित मंत्री हैं

युद्धक विमान से ब्रह्मोस उड़ान का सफल परीक्षण

विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल ब्रह्मोस ने 22 नवंबर 2017 को उस समय इतिहास रच दिया, जब भारतीय वायुसेना के प्रमुख युद्धक विमान सुखोई-30 एमकेआई से उसकी पहली उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। लक्ष्य-भेदन बंगाल की खाड़ी में स्थित था। गौरतलब है कि ब्रह्मोस विश्वस्तरीय हथियार है और जमीन, समुद्र और हवा में मारक क्षमता रखता है। उसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम ने संयुक्त रूप से निर्मित किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एएलसीएम (एयर लांच क्रूज मिसाइल) के प्रथम सफल परीक्षण पर हर्ष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस शानदार करतब के साथ जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, एसयू-30 एमकेआई से ब्रह्मोस एएलसीएम की प्रथम सफल फायरिंग पर हर्ष हुआ। इस शानदार करतब से जुड़े सभी व्यक्तियों को बहुत-बहुत बधाई। रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस शानदार उपलब्धि के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा विभाग (अनुसंधान एवं विकास) के सचिव डॉ. एस क्रिस्टोफर ने ब्रह्मोस के निर्माण में संलग्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी।

परिक्षण के समय भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों तथा डीआरडीओ और ब्रह्मोस के अधिकारियों सहित महानिदेशक (ब्रह्मोस) और ब्रह्मोस एयरोस्पेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक डॉ. सुधीर मिश्रा भी उपस्थित थे। ■

भारत और सिंगापुर के बीच नौसेनाओं के सहयोग पर अहम समझौता

भारत और सिंगापुर के बीच नौसेनाओं के सहयोग पर एक अहम समझौता हुआ, जिससे चीन की चिंता बढ़ सकती है। भारत के नौसैनिक जहाज अब सिंगापुर से फ्यूल ले सकते हैं। यह इसलिए अहम है कि शिपिंग रूट से भारत और सिंगापुर, दोनों के कारोबार के लिए दक्षिण चीन सागर अहम है, जिसे चीन अपना जल क्षेत्र होने का दावा करता है।

भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच 29 नवंबर को वार्ता के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के सहयोग पर यह समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की नौसैनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। लॉजिस्टिक सपॉर्ट भी मिलेगा। सिंगापुर के रक्षा मंत्री एन.ई. हेन ने कहा, 'हम अपने नौसैनिक अड्डे पर भारत के नौसैनिक जहाजों को आते-जाते देखना चाहेंगे। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने समुद्री आवाजाही की आजादी और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कारोबार को जरूरी बताया है। दोनों देशों की नौसेनाएं मलक्का स्ट्रेट में सहयोग बढ़ाएंगी। इस गलियारे के दोनों तरफ भारत और सिंगापुर का रोल बेहद अहम है। चीन का ज्यादातर तेल आयात मलक्का स्ट्रेट के संकरे समुद्री गलियारे से होता है।'

सिंगापुर के चीन से अच्छे कारोबारी संबंध हैं, जबकि वह सैन्य नजरिये से अमेरिका के करीब है। समुद्री इलाकों में चीन के कारण मिल रही चुनौतियों को देखते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ आते देखा जा रहा है। इन चारों देशों के साथ क्या सिंगापुर भी आ सकता है, इस अटकल को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सहयोग चाहते हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।

भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच 29 नवंबर को वार्ता के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के सहयोग पर यह समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की नौसैनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। लॉजिस्टिक सपॉर्ट भी मिलेगा।

सिंगापुर आसियान का सदस्य देश है। भारत इन दिनों आसियान के दूसरे सदस्यों वियतनाम, म्यांमार, मलयेशिया और इंडोनेशिया से भी रक्षा संबंध बढ़ा रहा है। चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (फिलिपींस, ब्रुनेई, मलयेशिया और विएतनाम) के बीच इस पर विवाद है और सिंगापुर विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सिंगापुर में अगले साल शंगरीला डायलॉग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र पर भारत का नजरिया रखेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र के करीब 50 देशों की मौजूदगी वाले इस सालाना सम्मेलन को डिफेंस डिप्लोमैसी के लिए बेहद अहम समझा जाता है, लेकिन भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था।

इस महत्वपूर्ण समझौते पर रक्षामंत्री श्रीमती सीतारमण एवं सिंगापुर के रक्षामंत्री डॉ. एनजी इंग हेन का संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि भारत और सिंगापुर के बीच दूसरी रक्षा मंत्री वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इसका उद्घाटन दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित संशोधित रक्षा सहयोग समझौते (डीसीए) के पश्चात किया गया, ताकि सिंगापुर सशस्त्र बल (एसएएफ) और भारतीय सशस्त्र बल के बीच लम्बे समय से लंबित रक्षा संबंध सुदृढ़ बनाये जा सकें।

दरअसल, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय वार्ता के परिणामस्वरूप सामुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, एक दूसरे की नाविक सुविधाओं से अस्थायी नियोजन एवं पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता में सहयोग बढ़ेगा। सिंगापुर के रक्षामंत्री डॉ. एनजी ने वायु सेना तथा सेना द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत सिंगापुर सशस्त्र बलों के भारत में प्रशिक्षण के

लिए निरंतर सहायता की प्रशंसा की। दोनों मंत्रियों ने इस वर्ष जनवरी में 11वीं सिंगापुर–भारत रक्षा नीति वार्ता के आधार पर वायु सेना द्विपक्षीय समझौते के नवीकरण का स्वागत किया और अगले वर्ष सेना द्विपक्षीय समझौते के सफलतापूर्वक नवीकरण की कामना की।

क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में दोनों मंत्रियों ने नौकायन और व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के समरूप सामुद्रिक स्वतंत्रता को बनाये रखने के महत्व की पुनः पुष्टि की। भारत आशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीडीएमएम)–प्लस में अहम भूमिका निभाता है। दोनों मंत्रियों ने सभी एडीएमएम–प्लस देशों को अनियोजित सामुद्रिक मुठभेड़ों के कूट के विस्तार तथा सैनिक वायुयानों के बीच अंतरिक्ष मुठभेड़ों के मार्ग निर्देश तैयार करने के सिंगापुर के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया ताकि गलत गणना के जोखिम को कम किया जा सके।

भारतीय समुद्री क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई भूमिका की प्रशंसा करते हुए डॉ. एनजी ने भारत के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसमें उनके सामुद्रिक क्षेत्र में निरंतर तथा संस्थानिक नाविक संलिप्तता एवं समान विचार वाले क्षेत्रीय/आशियान भागीदारों के साथ सामुद्रिक अभ्यास की व्यवस्था करना शामिल है। दोनों मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा धमकियों तथा विशेषकर आतंकवाद की धमकियों से निपटने के संयुक्त रूप से उपायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

दोनों मंत्रियों ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए अक्टूबर 2006 में भारत–सिंगापुर रक्षा प्रौद्योगिक स्टेयरिंग समिति की स्थापना के दौरान से हुई प्रगति को भी प्रशस्त किया। डॉ. एनजी ने भारत की इस पेशकश की भी प्रशंसा की जिसमें सिंगापुर को परीक्षण आयोजित करने तथा अनुसंधान एवं अभिकल्प परियोजनाओं के मूल्यांकन के आयोजनार्थ अपने परीक्षण केंद्रों और अवसंरचना का उपयोग करने की छूट दी है।

सिंगापुर और भारत ने इस वर्ष अगस्त में रक्षा उद्योग कार्यकारी समूह (डीआईडब्ल्यूजी) के लिए विचारार्थ विषयों पर हस्ताक्षर करके रक्षा उद्योग सहयोग में भी प्रगति की है। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के अंतरिक्ष, इलेक्टॉनिक्स तथा अन्य पारस्परिक महत्व के क्षेत्रों में भी अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करने पर सहमति जताई। डॉ. एनजी ने स्थिर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के भारत के विजन को स्पष्ट करने के लिए 2018 सांगरी–ला वार्ता में मुख्य वक्ता बनना स्वीकार करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की। ■

15 दिसम्बर से 5 जनवरी तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसम्बर, 2017 से 5 जनवरी, 2018 तक आयोजित करने की सिफारिश की है। यह अवधि सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकता के अधीन होगी। संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने सीसीपीए की बैठक के बाद यह जानकारी दी। श्री अनंत कुमार ने बताया कि शीतकालीन सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी और यह 22 दिन तक चलेगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें संसद के आगामी सत्र के लिए विधायी कार्यसूची पर विचार किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अनंत कुमार ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है, जबकि विधानसभा चुनावों के चलते संसद के सत्र को उसी समय आयोजित नहीं किया गया हो। यह पद्धति अतीत में विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक अवसरों पर अपनाई जाती रही है। श्री अनंत कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे महत्वपूर्ण विधेयकों पर उपयोगी और रचनात्मक बहस में सहयोग करें और संसद के दोनो सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करें।

तीन तलाक और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री अनंत कुमार ने कहा कि भारत की जनता की यह प्रबल इच्छा है कि इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद कानून बनाए

और सरकार लोगों की इच्छा पूरी करने के प्रति वचनबद्ध है।

आगामी शीतकालीन सत्र में निम्नांकित अध्यादेशों के स्थान पर तीन विधेयक पेश किए जाएंगेः

- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अध्यादेश, 2017 (02.09.2017 को जारी)
- ऋण शोधन और दिवाला संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017
- भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 ■

15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की योजनाओं से जुड़ेः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर को कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, उज्ज्वल भारत के भविष्य और न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए वह बड़ी से बड़ी राजनीतिक कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने यह उल्लेख कालाधन पर लगाम लगाने के लिये उठाने गए कदमों के संदर्भ में किया है।

श्री मोदी ने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कालाधन पैदा करना, व्यवस्था की कमजोरी की वजह से भ्रष्टाचार करने की संभावना कम से कम रह जाएगी। प्रधानमंत्री ने हिन्दुस्टान टाइम्स लीडरशीफ समिट को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद देश में जिस तरह का व्यवहारिक बदलाव आया है उसे आप खुद महसूस कर रहे होंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब भ्रष्टाचारियों को कालेधन के लेन-देन से पहले डर लग रहा है। उनमें पकड़े जाने का भय आया है। जो कालाधन पहले समानांतर अर्थव्यवस्था का आधार था, वह नोटबंदी के बाद औपचारिक अर्थव्यवस्था में आया है।

उन्होंने कहा कि जिस दिन देश में ज्यादातर खरीद-फरोख्त, पैसे के लेन-देन का एक तकनीकी और डिजिटल पता हो गया, उस दिन से संगठित भ्रष्टाचार काफी हद तक थम जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब योजनाओं में गति होती है, तभी देश में प्रगति आती है। कुछ तो परिवर्तन आया होगा, जिसकी वजह से सरकार की तमाम योजनाओं की स्पीड बढ़ गई है। साधन वही हैं, संसाधन वहीं हैं, लेकिन व्यवस्था में रफ्तार आ गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार, नौकरशाही में भी एक नई कार्य-संस्कृति तैयार कर रही है। उसे ज्यादा जवाबदेह बना रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 1800 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। इतने रुपए किसी और सरकार ने दिए होते तो उसे मसीहा बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया होता, लेकिन गरीबों के लिए इतना बड़ा काम हुआ, मुझे नहीं लगता इस पर किसी ने ध्यान दिया होगा। ये भी एक सच है जिसे मैं स्वीकार करके चलता हूं। एक और उदाहरण LED बल्ब का है। पहले की सरकार में जो LED बल्ब तीन सौ-साढ़े तीन सौ का बिकता था, वो अब एक मध्यम वर्ग के परिवार को लगभग 50 रुपए में उपलब्ध है। उजाला योजना शुरू होने के बाद से देश में अब तक लगभग 28 करोड़ LED बल्ब बिक चुके हैं। इन बल्बों से लोगों को 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि बचत पर, बिजली बिल कम होने पर कुछ समय में फुल स्टॉप लग जाएगा। जो बचत हो रही है, वो होती ही रहेगी। ये बचत भी अब परमानेंट है। पहले ही सरकारों को ऐसा करने से किसी ने रोक रखा था या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूं कि सिस्टम में स्थाई परिवर्तन लाने फैसले

लेने से, देशहित में फैसला लेने से, किसी के रोके नहीं रुकेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि देश जादू की छड़ी घुमाकर नहीं बदला जा सकता, वो हताशा और निराशा से भरे हुए हैं। ये अप्रोच हमें कुछ भी नया करने से रोकती है। ये अप्रोच हमें फैसला लेने से रोकती है। इसलिए इस सरकार की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग है। जैसे यूरिया की नीम कोटिंग की ही बात करें। पहले की सरकार में यूरिया की 35 प्रतिशत नीम कोटिंग होती थी, जबकि पूरे सिस्टम को पता था कि 35 प्रतिशत नीम कोटिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यूरिया का डायवर्जन रोकना है, फैक्ट्रियों में जाने से रोकना है, तो उसकी सौ प्रतिशत नीम कोटिंग करनी ही होगी, लेकिन ये फैसला पहले नहीं हुआ। इस सरकार ने फैसला लिया यूरिया की पूरी तरह नीम कोटिंग का। इस फैसले से ना सिर्फ यूरिया का डायवर्जन रुका है, बल्कि उसकी अपनी क्षमता बढ़ गई है। अब किसान को उतनी ही जमीन के लिए कम यूरिया डालना पड़ता है। इतना ही नहीं, कम यूरिया डालने के बावजूद उसकी पैदावार बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम देश में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिस पर आकर किसी भी जगह का किसान कहीं से भी अपनी फसल बेच सके। ये देश में बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। e-Nam यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से अब तक देश की साढ़े चार सौ से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा चुका है। भविष्य में ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने में बहुत मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सरकार ने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए, स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि खेत या बाग़ में पैदा होने के बाद जो अनाज या फल मंडी तक पहुंचने से पहले खराब हो जाता है, उसे बचाया जाए। सरकार इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी मजबूत कर रही है, ताकि किसान का खेत एक इंडस्ट्रियल यूनिट की तरह भी काम करें। ■

अब हम देश में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिस पर आकर किसी भी जगह का किसान कहीं से भी अपनी फसल बेच सके। ये देश में बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। e-Nam यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से अब तक देश की साढ़े चार सौ से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा चुका है।

लंदन में नमामि गंगे को मिला जबर्दस्त समर्थन

स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का सहयोग

गंगा, नदी विकास, जल संसाधन, राजमार्ग, नौपरिवहन एवं यातायात मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बताया कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के कारोबारियों ने स्वच्छ गंगा अभियान से संबद्ध करीब 500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में सहयोग के लिये प्रतिबद्धता जतायी है। श्री गडकरी ने कहा कि पटना, कानपुर, हरिद्वार और कोलकाता शहर में नदी तटों में सुधार और घाटों के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटेन के चार प्रमुख उद्योगपतियों ने ली है। पटना में जन्मे वेदांता समूह के प्रमुख श्री अनिल अग्रवाल ने शहर में नदी तटों के पुनरुद्धार में अपना समर्थन देने का संकल्प जताया है। नौपरिवहन क्षेत्र के पूंजीपति श्री रवि मेहरोत्रा ने कानपुर में इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी ली है। हिंदुजा समूह हरिद्वार में घाटों को विकसित करेगा और इंडोरामा समूह के प्रमुख श्री प्रकाश लोहिया कोलकाता के गंगा सागर के पुनरूद्धार की जिम्मेदारी उठाएंगे।

श्री गडकरी ने ब्रिटेन की तीन दिवसीय यात्रा के समापन पर कहा, "हमें इन परियोजनाओं में 500 करोड़ रुपये से अधिक के सहयोग का वादा किया गया है और मैं सभी प्रवासी भारतीयों से अपील करता हूं कि वह दिल से नमामि गंगे मुहिम में हिस्सा लें।" कारोबारी इस परियोजनाओं को अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एजेंडा के तौर पर लेंगे और हर शहर के लिये योजनाओं को अंतिम रूप देने पर भारत सरकार के साथ काम करेंगे।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के कारोबारियों के अलावा ब्रिटेन स्थित कंपनियों- लिंडन वाटर, सेल्टिक रिन्युएबल्स, मेबीफार्म, एनवीएच टेक्नोलॉजीज, एवं आर्काटैप ने भी इन परियोजनाओं में सहयोग का वादा किया है। इन कंपनियों ने स्वच्छ गंगा कार्यक्रम के लिये प्रौद्योगिकी साझा करने का वादा किया है। ब्रिटेन के बाद मंत्री भारतीय समुदाय को स्वच्छ गंगा से संबद्ध परियोजनाओं से जोड़ने के लिये दुबई, सिंगापुर और अमेरिका में भी इसी तरह के रोडशो के आयोजन की योजना बना रहे हैं। ■

डिजिटल प्रौद्योगिकी एक क्रांतिकारी साधनः नरेन्द्र मोदी

उमंग एप लॉन्च

उमंग एक नजर में –

- सभी सरकारी सेवाओं में एकरूप यूजर सहज इंटरफेस
- 33 विभागों की 162 सेवाएं/एप्लीकेशन तथा चार राज्य
- केन्द्र राज्य तथा उपयोगिता सेवाओं से 1200 से अधिक विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एक मात्र मोबाइल एप
- 13 भारतीय भाषाओं में समर्थित और मांग पर उपलब्ध
- यूएसएसडी के माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले फीचर फोनों को जल्द समर्थन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 नवंबर को नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर पांचवें वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महामहिम श्री रानिल विक्रमसिंघे, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी और कानून तथा विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, दूरसंचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री के.जे. अल्फोंस तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के महासचिव श्री हॉउ लीन झाओ तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने उमंग एप भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य एक ही मोबाइल एप पर 162 सरकारी सेवाओं को लाना है, ताकि हमारे नागरिकों के मोबाइल फोन पर सरकारहॉउ की पहुंच हो सके।

यह पांचवां जीसीसीएस सम्मेलन था। इसकी थीम सभी के लिए साइबरः सतत विकास के लिए सुरक्षित और समावेशी साइबर स्पेस थी। दरअसल, साइबर स्पेस पर पांचवें वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक साइबर नीति में समावेशन तथा मानव अधिकारों के महत्व को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी यह जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में साइबर स्पेस ने किस प्रकार विश्व का रूप परिवर्तित कर दिया है। यहां बैठे लोगों में से वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों को 70 और 80 के दशकों में बड़े-बड़े कंप्यूटर सिस्टमों के मेनफ्रेम याद होंगे, तब से काफी कुछ बदल गया है। 90 के दशक में ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर ने एक नई क्रांति को जन्म दे दिया है। यह सोशल मीडिया के आगमन के कारण हुआ था और मोबाइल फोन के आगमन डाटा स्टोरेज और संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्द आजकल आम बन गए हैं। यह उस निरंतर बदलाव के सूचक शब्द हैं जो शायद बहुत अधिक तेज गति से हो रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में इन तीव्र विकासों ने भारत में भी बहुत बदलाव किया है और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रतिभाओं को विश्व भर में पहचान मिली है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनियों ने भी विश्व में अपना परचम लहराया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, डिजिटल प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़े साधन के रूप में उभरी है। इसने कुशल सेवा सुपुर्दगी और गवर्नेंस के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी पहुंच को सुगम बनाने के साथ-साथ उसमें सुधार कर रही है और यह व्यापार और अर्थव्यवस्था के भविष्य को भी बदलने में सहायता कर रही है। इन सभी माध्यमों से, यह समाज के वंचित समूहों को अधिक अवसर प्रदान कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का मौलिक दर्शन सबका साथ, सबका विकास है। डिजिटल भारत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। डिजिटल भारत के हमारे प्रधानमंत्री के विजन ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति को नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। भारत का डिजिटल विकास सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी से लेकर 1.3 बिलियन लोगों को डिजिटल रूप में आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने तक हुआ है।

श्री प्रसाद ने कहा कि समावेशी विकास में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार और सेवा डिलीवरी प्रणाली में चोरी थी। जन-धन बैंक खाता, आधार, डिजिटल पहचान और मोबाइल फोन की तिकड़ी ने इस समस्या का कारगर समाधान किया है। वित्तीय लाभों को गरीब लोगों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान करने से 515 मिलियन लोगों को लाभ हुआ है और पिछले तीन वर्षों में करदाताओं के 9 मिलियन डॉलर की बचत हुई है। ■

आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को आकाशवाणी से 'मन की बात' कार्यक्रम के 38वें संस्करण में कहा कि 26 नवम्बर हमारा संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान-सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसलिए तो हम, उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। आज का दिन संविधान-सभा के सदस्यों के स्मरण करने का दिन है। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग तीन वर्षों तक परिश्रम किया और जो भी उस डिबेट को पढ़ता है, हमें गर्व होता है कि राष्ट्र को समर्पित जीवन की सोच क्या होती है!

श्री मोदी ने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विविधताओं से भरे अपने देश का संविधान बनाने के लिए उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया होगा? सूझ-बूझ, दूरदर्शिता के दर्शन कराए होंगे और वो भी उस समय, जब देश ग़ुलामी की जंज़ीरों से मुक्त हो रहा था। इसी संविधान के प्रकाश में संविधान-निर्माताओं, उन महापुरुषों के विचारों के प्रकाश में नया भारत बनाना, ये हम सबका दायित्व है। हमारा संविधान बहुत व्यापक है। शायद जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, प्रकृति का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उससे अछूता रह गया हो। सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता, हमारे संविधान की पहचान है। यह हर नागरिक, ग़रीब हो या दलित, पिछड़ा हो या वंचित, आदिवासी, महिला सभी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है और उनके हितों को सुरक्षित रखता है।

उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का

हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करें। नागरिक हों या प्रशासक, संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ें। किसी को किसी भी तरह से क्षति ना पहुंचे- यही तो संविधान का संदेश है। आज संविधान-दिवस के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की याद आना तो बहुत स्वाभाविक है। इस संविधान-सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर 17 अलग-अलग समितियों का गठन हुआ था। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितियों में से एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर संविधान की उस ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे।

अक्षरशः पालन करें। नागरिक हों या प्रशासक, संविधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ें। किसी को किसी भी तरह से क्षति ना पहुंचे- यही तो संविधान का संदेश है। आज संविधान-दिवस के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की याद आना तो बहुत स्वाभाविक है। इस संविधान-सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर 17 अलग-अलग समितियों का गठन हुआ था। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितियों में से एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर संविधान की उस ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। आज हम भारत के जिस संविधान पर गौरव का अनुभव करते हैं, उसके निर्माण में बाबासाहेब अंबेडकर के कुशल नेतृत्व की अमिट छाप है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज के हर तबके का कल्याण हो।

श्री मोदी ने कहा कि 6 दिसम्बर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम हमेशा की तरह उन्हें स्मरण और नमन करते हैं। देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में बाबासाहेब का योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 दिसम्बर को सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि है। किसान-पुत्र से देश के लौह-पुरुष बने सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का बहुत असाधारण कार्य किया था। सरदार साहब भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे। वे मूलभूत अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर बनी एडवाइजरी कमिटी के भी अध्यक्ष थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26/11 हमारा संविधान-दिवस है, लेकिन ये देश कैसे भूल सकता हैं कि नौ साल पहले 26/11 को आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला बोल दिया था। देश उन बहादुर नागरिकों, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उन हर किसी का स्मरण करता है, उनको नमन करता है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह देश कभी उनके बलिदान को नहीं भूल सकता। आतंकवाद आज विश्व के हर भू-भाग में और एक प्रकार से प्रतिदिन होने वाली घटना का, एक अति-भयंकर रूप बन गई है। हम, भारत में तो गत 40 वर्ष से आतंकवाद के कारण बहुत कुछ झेल रहे हैं। हज़ारों हमारे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था तो दुनिया के बहुत लोग थे, जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें, आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रही हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ़ भारत ही नहीं विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर, आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी ये ही तो ये धरती है, जिसने अहिंसा और प्रेम का संदेश दुनिया को दिया है। आतंकवाद और उग्रवाद, हमारी सामाजिक संरचना को कमज़ोर कर, उन्हें छिन्न-भिन्न करने का नापाक प्रयास करते हैं और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का अधिक जागरूक होना समय की मांग है। ■

पत्रकार-वार्ता

'जल्दी से जल्दी श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई होनी चाहिए : अमित शाह'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 दिसंबर को अहमदाबाद स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और श्री राम जन्मभूमि विषय पर कांग्रेस पार्टी से अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वह श्री राम जन्मभूमि विषय की जल्द सुनवाई के पक्ष में या नहीं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज देश की सर्वोच्च अदालत में श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि समग्र देश की जनता का भाव ये है कि यह सुनवाई जल्द-से-जल्द समाप्त हो और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला श्री राम जन्मभूमि के लिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द देश और दुनिया के सामने आये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हित में श्री सिब्बल ने एक बार सुनवाई से अपने आप को अलग करने की धमकी सर्वोच्च अदालत में दी थी। यह दर्शाता है कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण को रोकने की दिशा में कांग्रेस की तीव्रता कितनी है।

श्री शाह ने कहा कि आज एक आश्चर्यजनक दलील कांग्रेस के नेता और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील श्री कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत के सामने रखी है कि जुलाई 2019 तक अर्थात जब तक आगामी लोक सभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस किसी विवादित मुद्दे पर अलग प्रकार का स्टैंड लेना चाहती है, तब श्री कपिल सिब्बल को आगे कर देती है। उन्होंने कहा कि 2जी घोटाला हुआ तब भी जीरो लॉस की थ्योरी लेकर कपिल सिब्बल आगे आए थे। गुजरात में जब आरक्षण का मसला आया तब भी 50% से ज्यादा आरक्षण संभव है, ऐसा एक ओपिनियन लेकर कपिल सिब्बल आए और अब जब कांग्रेस को श्री राम जन्मभूमि केस के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं, तब भी कपिल सिबल कांग्रेस पार्टी की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के रुप में आए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि वह श्री राम जन्मभूमि केस की जल्द सुनवाई पर सहमत है या नहीं, या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि 2019 के आम चुनाव तक श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई ना हो।

श्री शाह ने कहा कि मैं समझ भी नहीं सकता कि जब सम्पूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद हो चुका है और केस की सुनवाई तीन जज की बेंच करेगी, यह भी निर्णय आज कर दिया गया है तो सुनवाई को रोकने से क्या हासिल है? उन्होंने कहा कि यह सुनवाई जितनी जल्द होगी, इस देश की जनता को श्री राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी उतनी ही जल्दी मालूम पड़ जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर अपना अधिकृत स्टैंड स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी जोकि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, वे गुजरात में मंदिर-मंदिर जाकर अभी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर गुजरात में राहुल गांधी के मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरे रवैया जनता के सामने उजागर हो गया है।

श्री शाह ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के घोषित होने वाले अध्यक्ष श्री राहुल गांधी से अपील करना चाहूंगा कि वे स्वयं इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जल्दी से जल्दी श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई होनी चाहिए, सर्वोच्च अदालत का फैसला जल्द आना चाहिए और वहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।

पत्र-पत्रिकाओं से...

जीडीपी का छक्का

जीडीपी में थोड़ी रफ्तार आने से देश को राहत मिली है। वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर लगातार गिरावट का सिलसिला तोड़कर 6.3 फीसदी पर पहुंच गई। पिछली पांच तिमाहियों में यह 7.9 प्रतिशत से गिरती हुई 5.7 प्रतिशत तक आ गई थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आने वाली नकारात्मक खबरों ने लोगों में कई तरह की आशंकाएं भर दी थीं, हालांकि शेयर बाजार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वह लगातार चढ़ता ही रहा। इधर कुछ समय पहले 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत के अच्छे प्रदर्शन और मूडीज की पॉजिटिव रेटिंग ने थोड़ी उम्मीद जगाई और अब जीडीपी के आंकड़े ने साबित किया है कि चीजें पटरी पर लौटनी शुरू हो गई हैं।

— (नवभारत टाइम्स, 4 दिसंबर, २०17)

निकायों के नतीजे

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की ही तरह जोरदार जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे विकास की जीत कहा है तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रधानमंत्री के विकास के 'विजन' और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रणनीतिक कुशलता का परिणाम बताया है। इन औपचारिक प्रतिक्रियाओं को परे रख दिया जाए तो भी यह मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस जीत ने योगी सरकार के सात महीनों के कामकाज पर अपनी मुहर लगा दी है।

— (जनसत्ता, २ दिसंबर, २०17)

विश्व धरोहर कुंभ

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज) का दर्जा दिया है। कुंभ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान योग और नवरोज के बाद किसी भारतीय परंपरा को मिला लगातार तीसरा खिताब है। यूनेस्को की विशेषज्ञ समिति के अनुसार कुंभ मेला धरती पर होने वाला सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक सम्मेलन है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के भाग लेते हैं। एक धार्मिक आयोजन के तौर पर कुंभ में जैसी सहिष्णुता और समायोजन नजर आता है, वह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि आदि शंकराचार्य ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। कुंभ को विश्व स्तर पर महत्व मिलना भारत के लिए एक उपलब्धि है।

— (नवभारत टाइम्स, 9 दिसंबर, २०17)

कश्मीर में पथराव करने वालों के बीच उम्मीद का उदाहरण

कश्मीर में पुलिस वालों पर पथराव करने वाली लड़की अफसान आशिक के महिला फुटबॉल टीम का कप्तान बनने से उम्मीद का उदाहरण कायम हुआ है। इस बदलाव व कामयाबी ने साबित किया है कि अगर समाज और सरकार टकराव छोड़कर सहयोग के रास्ते पर चलें तो क्या नहीं हो सकता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर अफसान ने कश्मीर में भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थान की मांग की है और अब वह पुलिस और सरकार से लड़ने की बजाय मुल्क और सूबे का नाम रोशन करना चाहती है। निश्चित तौर पर अफसान का यह बदलाव खुशी देता है और उसी के साथ अगर हम पुलिस और युवाओं के हर टकराव को देशद्रोह मानने की बजाय गुस्से की अभिव्यक्ति मानकर चलें तो समस्या के समाधान में ज्यादा कामयाबी मिल सकेगी। बहुत अच्छी बात है कि हिंसक राजनीति में लगी युवा ऊर्जा खेल की प्रतिस्पर्धा में लगे और पदक और ट्राफियां जीते।

— (दैनिक भास्कर, 7 दिसंबर, २०17)

स्फुट विचार...

अब हमें समाज के कमजोर वर्गों में अपना आधार बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें अधिक–से–अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए तथा उन्हें उस ओर समतावादी भारतीय परिवार में शामिल करना चाहिए। जिसमें जातीय तथा जनजातीय वर्ग पूर्ण सद्भाव के साथ मिलकर रहें तथा वे एक दूसरे से न झगड़ें।

— कुशाभाऊ ठाकरे

पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन इसके लिए नियोजन की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा। बुनियादी जरूरत की चीजों और सेवाओं का उत्पादन जनसाधारण द्वारा होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी।

— अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)............................... (2)...............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में 'डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र' को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

सूरत, गुजरात में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17